सुविचार

ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है।

-मुंशी प्रेमचंद

Daily

सच के हक में...

THE PHOTON NEWS

द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi ● Sunday, 24 August 2025 ● Year : 03 ● Issue : 219 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com

E-Paper : epaper.thephotonnews.com

SARAFA

सोना	:	9,480
चांदी	:	130.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

अनिल अंबानी के घर पर अब सीबीआई ने मारा छापा

MUMBAI : निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के प्रवर्तक निदेशक अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कथित बैंक धोखाधड़ी के से जुड़े मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को आरकॉम के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मुंबई स्थित उनके ठिकानों पर छापा मारा। जानकारी के अनुसार, सीबीआई की टीमें मुंबई में आरकॉम और उसके प्रवर्तक निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। अनिल अंबानी पर आरोप है कि इस धोखाधड़ी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को 2000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने किया गिरफ्तार

BENGALURU : कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को सिक्किम से गिरफ्तार किया। वीरेंद्र की गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत हुई है। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप है। ईडी ने शुक्रवार को वीरेंद्र के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को 12 करोड़ रुपए कैश और 6 करोड़ की गोल्ड ज्वैलरी मिली। साथ ही एक करोड़ की फॉरेन करेंसी भी बरामद की है। चार गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। केसी वीरेंद्र कर्नाटक की चित्रदुर्ग विधानसभा में विधायक हैं। बताया गया है कि विधायक की गोवा में कसीनो कारोबार में हिस्सेदारी है।

उत्तराखंड के थराली में बादल फटने से भारी तबाही

DEHRADUN : उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार आधी रात को चमोली जिले के थराली तहसील क्षेत्र के टूनरी गदेरे में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यहां थराली बाजार और आसपास के क्षेत्र में भारी मलबा आ गया। मलबे की चपेट में आने से एसडीएम आवास सहित कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। दुकानों में मलबा भर गया। कई वाहन भी मलबे में दब गए। मलबे में दबने से एक युवती की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है।

आफत : लगातार हो रही भारी बारिश ने जन-जीवन को किया प्रभावित, घरों में घुसा पानी

झारखंड के 15 जिलों में बाढ़ का खतरा

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में मानसून एक बार फिर फुल मिजाज से अपना असर दिखा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के ऊपर बने निम्न दबाव की वजह से पिछले दो दिनों से राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से जन-जीवन काफी प्रभावित हुआ है। गुरुवार रात से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले तीन-चार दिनों तक भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 15 जिलों में बाढ़ के खतरे की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में बाढ़ की आशंका जताई है, उनमें बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, रांची, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। पिछले दो दिनों में राज्य के चतरा, रांची, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा और लातेहार सहित कई जिलों में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं, सड़कों पर पानी भर गया है। शहरी क्षेत्र के निचले इलाके में पानी भरने से लोगों के घर में पानी घुस गया है। बारिश ने चतरा के चार प्रखंडों पत्थलगडा, गिद्धौर, कान्हाचट्टी और ईटखोरी में तबाही मचाई। बारिश से न केवल चतरा बल्कि रांची में बारिश परेशानी का सबब बन गई है।

-पेज 03 व 04 भी पढ़ें।

रांची सहित कई शहरों में सड़कों पर हुआ जल-जमाव, आवागमन में बढ़ी दिक्कत

धुर्वा-तिलैया डैम के खोल दिए गए फाटक, स्वर्णरेखा व खरकई नदी का बढ़ गया जलस्तर

- चुटिया और नामकुम को जोड़ने वाली सड़क पर बने पुल के ऊपर बह रहा पानी
- पंचशीलनगर, हिंदपीढ़ी, मोरहाबादी और कोकर सहित कई मोहल्लों में लोग परेशान
- मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों तक भारी बारिश की जताई आशंका, चेतावनी जारी

पिस्कानगड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का स्लैप गिरने से आवागमन बाधित

लगातार बारिश की वजह से रांची में स्वर्णरेखा का जलस्तर बढ़ रहा है। चुटिया और नामकुम को जोड़ने वाली सड़क पर बने पुल के ऊपर पानी बह रहा है। धुर्वा डैम के सभी गेट को खोला गया है। पहले पानी ओवरफ्लो होकर बहने लगा था। रांची के पंचशीलनगर, हिंदपीढ़ी, मोरहाबादी और कोकर सहित कई मुहल्ले में बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया, जिससे लोगों का सामान भीग गया है। भारी बारिश के कारण रांची के जगन्नाथपुर रोड में भी दरार आ गई है। पिस्कानगड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का स्लैप गिर जाने की वजह से इस सड़क पर आवागमन बाधित हो गया है।

तिलैया डैम में पानी खतरे के निशान के ऊपर, पांच जिलों के लिए अलर्ट

कोडरमा के तिलैया डैम में भी पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में एहतियातन शनिवार की सुबह तिलैया डैम के पांच फाटक खोले गए हैं। फाटक खोलने के कारण निचली इलाकों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। इसको लेकर प्रशासन ने पांच जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इनमें बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा शामिल हैं।

आज इन जिलों में भारी वर्षा

मौसम विभाग ने 24 अगस्त को राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, एवं गिरिडीह शामिल हैं।

कल इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी

मौसम विभाग के अनुसार, 25 अगस्त को भी राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल हैं।

नौकरशाही

आखिर शौक बड़ी चीज है

डॉ. ब्रजेश मिश्र

झारखंड की नौकरशाही में सीनियरिटी के पायदान पर कदम रखकर भी कुछ अधिकारी सत्ता-संतुलन साधन के मोर्चे पर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। ज्यादातर इनकी अपनी गलती इनके लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। जानें क्या कुछ चल रहा है अंदरखाने, द फोटोन न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर की कलम से।

गुरु पिछले कुछ समय से मौन थे। वनांचल के राजनीतिक गलियारे से एक के बाद एक दुखद सूचनाएं आ रही थीं। लिहाजा पूरा मूड-माहौल गमगीन हो गया था। अब स्थितियां सामान्य होने की ओर हैं। कुछ समय का ठहराव गतिमान होने लगा है। गुरु फिर अपने ट्रैक पर लौट आए। हल्की-हल्की बारिश के बीच घर के बरामदे में कुर्सी लगाकर अखबार पढ़ रहे थे। दरबार खाली दिखा। सो, खबर की खोज में धीरे-धीरे चौखट की सीढ़ी चढ़ गया। गुरु भी एकांत से शायद भन्ना गए थे। नजर पड़ते ही बड़े उत्साह से स्वागत किया। बोले- आओ, आओ, बड़े दिन बाद दिखे। हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बगल की कुर्सी खींचकर चुपचाप बैठ गया। बातचीत गुरु ने ही शुरू की। पूछा- और बताओ क्या चल रहा है नौकरशाहों के दरबार में? बात आगे बढ़ाने के लिए जवाब देना था। सो दिया, 'चल तो बहुत कुछ रहा है गुरु। बस चलकर चौहद्दी से बाहर नहीं आ रहा।' बात पूरी होते ही गुरु खिलखिलाकर हंस दिए। बोले- अरे तो हमसे पूछ लेते, हम किस मर्ज की दवा हैं? गुरु का इशारा मिलते ही सवाल परोस दिया। सिस्टम में एक बिहार वाले साहब हैं। पिछले कई सालों से व्यवस्था को साधने की

कोशिश कर रहे हैं। बेचारे जब भी पूरा गुणा-गणित लगाकर अपना फार्मूला सेट करते हैं, अचानक समीकरण पलट जाता है। आखिर इनका जोड़-घटाव पूरी तरह फिट बैठता क्यों नहीं? गुरु संकेत समझ गए। बोले- देखो, जिन महोदय की तुम बात कर रहे हो, उनके पैर में चक्र है। लिहाजा एक जगह टिक कर रहना उनके काल-क्रम में नहीं है। जहां तक उनके समीकरण की बात है, तो एक कंफ्यूजन उन्हें अपने अध्ययन काल से है। अब तक नहीं समझ पाए कि वह साहित्य के विद्यार्थी हैं या विज्ञान के। लिहाजा कई बार माहौल से उलट व्याख्यान दे देते हैं। सभा मंडली को इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि जानबूझकर गुस्ताखी की गई है।

रही-सही कसर साहब का सोशल मीडिया प्रेम पूरा कर देता है। टीवी पर पहले एक विज्ञापन आता था, जिसमें एक ब्रांड के प्रचार में कहा जाता था- शौक बड़ी चीज है। देखने वाले हर शख्स को पता था कि यह खतरनाक है। शायद इसके पीछे शौक के लिए खतरे की चुनौती स्वीकार करने का संदेश था। साहब का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। बार-बार खतरे के मुहाने पर खड़े होकर शौक जाहिर करते रहते हैं। कई बार कुछ साथ के लोग सहयोग में योग खराब कर देते हैं। बहरहाल, साहब के साथ अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों की तन्हाई के बाद अपने को कूल कर लेते हैं। गुरु की सभा से उठकर चलना शुरू किया तो सवाल का जवाब साथ था।

अजरबैजान से झारखंड लाया गया मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मयंक सिंह

मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा

- रामगढ़ के अपर न्यायिक दंडाधिकारी संदीप बर्मन की अदालत में किया गया पेश, नहीं मिली रिमांड
- गैंगस्टर ने खुद को मयंक सिंह मानने से किया इनकार, कोर्ट ने भेजा जेल
- झारखंड के विभिन्न जिलों में मयंक के खिलाफ दर्ज किए गए हैं 48 मामले
- एटीएस एसपी ऋषभ झा बोले- सभी थानों में दर्ज मामलों की हो चुकी है समीक्षा

PHOTON NEWS RANCHI : शनिवार को झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा को अजरबैजान से झारखंड लाया गया। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मयंक सिंह को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। रांची एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा में उसे रामगढ़ भेजा गया। गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को झारखंड एटीएस की टीम 1:50 बजे रामगढ़ कोर्ट लेकर पहुंची। एंटी लैंड माइंस वाहन से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे अपर न्यायिक दंडाधिकारी संदीप बर्मन की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में गैंगस्टर ने साफ कहा कि वह मयंक सिंह नहीं है। इस नाम का कोई और व्यक्ति होगा। कोर्ट में एटीएस और गैंगस्टर के वकील की दलीलें सुनने के बाद उसे रामगढ़ उपकारा भेजने का निर्देश दिया। एटीएस की तमाम दलीलों के बावजूद कोर्ट ने गैंगस्टर की रिमांड नहीं दी। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा खुद मयंक सिंह को लाने अजरबैजान गए हुए थे। मयंक सिंह के खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों में कुल 48 मामले दर्ज हैं।

-पेज 03 भी पढ़ें।

नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा-

कम समय में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में की उल्लेखनीय प्रगति

NEW DELHI @ PTI : शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे की शुभकामनाएं देते हुए देश की स्पेस पावर और मिशन गगनयान का जिक्र किया। कहा कि भारत अपना एस्ट्रोनॉट पूल भी तैयार कर रहा है। मैं युवाओं से इस पूल से जुड़ने की अपील करता हूं। इसरो ने युवाओं की स्पेस फील्ड में रुचि बढ़ाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष हैकथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज की पहल की है। ये सराहनीय है। इस बार स्पेस डे की थीम आर्यभट्ट से गगनयान तक है। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। उन्होंने कहा, कम समय में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

● इसरो ने दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का लॉन्च किया मॉडल

दर्दनाक : शाहजहांपुर के दनियावां स्टेट हाईवे-4 पर सिगरियावा स्टेशन के पास हादसा

पटना में ट्रक-ऑटो में टक्कर, 9 लोगों की मौत

PHOTON NEWS RANCHI : शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर में नौ लोगों की जान चली गई। चार लोग घायल हो गए। हादसा शाहजहांपुर के दनियावां हिलसा स्टेट हाईवे-4 पर सिगरियावा स्टेशन के पास हुआ। आमने-सामने की टक्कर में सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल में दम तोड़ा। मरने वालों में 8 महिलाएं और ऑटो ऑटो ड्राइवर शामिल हैं। मृतकों में मां-बेटी भी है। मृतकों में गंगा देवी (50), संजू देवी (60), दीपिका पासवान (35), कुसुम देवी (48), कंचन पांडे, बबीता देवी, रेनू देवी, उदेशा देवी, ड्राइवर चंदन कुमार (30) शामिल हैं।

चार जख्मी, मृतकों में मां-बेटी सहित आठ महिलाएं और ऑटो ड्राइवर शामिल

ऑटो से बहकर सड़क पर फैल गया खून

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सड़क पर लाशें पड़ी थीं और उससे लिपटकर परिजन रोए जा रहे थे। टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी से खून बहकर कर सड़क पर फैल गया। सड़क किनारे कुछ महिलाओं की लाश पड़ी थीं। सड़क पर मृतकों के सामान, चप्पलें बिखरी पड़ी थीं।

● घायलों को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती, सबकी हालत गंभीर

गंगा स्नान के लिए जा रहे थे सभी

नालंदा से गांव की महिलाएं तीज पर्व को लेकर गंगा स्नान करने से फतुहा के त्रिवेणी जा रही थीं। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। वे घटनास्थल पर किसी को वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। मृतक के परिजनों को हिलसा एसडीएम अमित कुमार पटेल ने तत्काल 20 हजार रुपये का चेक दिया है।

हेल्थ अलर्ट चिकित्सा जगत के लिए दुर्लभ बीमारी है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएंसेफलाइटिस

अमीबा का दिमाग तक पहुंचना बन जाता जान पर खतरा

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : जीव विज्ञानियों के अनुसार, अमीबा एक एककोशिकीय जीव है। यह निरंतर अपना आकार बदलने में सक्षम होता है और स्यूडोपोडिया (नकली पैर) के माध्यम से चलता और भोजन ग्रहण करता है। यह एक यूकेरियोटिक जीव है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक परिभाषित केंद्रक होता है। अमीबा विभिन्न प्रकार के जलीय वातावरणों में पाए जाते हैं। ये तालाबों, कुओं, झीलें और नदियों में पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति खारे पानी में भी होती है। ये प्रोटिस्ट नामक जीव समूह से संबंधित हैं। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। सामान्यत ये पेट संबंधी बीमारियां अधिक पैदा करते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर के अनुसार, अमीबा अगर इंसान के दिमाग तक पहुंच जाए तो जान को खतरा उत्पन्न हो जाता है। नेग्लेरिया फाउलेरी या दिमाग खाने वाले अमीबा से होने वाली इस दुर्लभ बीमारी को प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएंसेफलाइटिस (पीएएम) कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में सिरदर्द, बुखार, मितली आने जैसे लक्षणों के कारण आमतौर पर इस बीमारी का जल्द पता नहीं लग पाता।

प्रारंभिक अवस्था में सिरदर्द, बुखार, मितली आने जैसे लक्षण के बाद गंभीर होती है स्थिति

9 साल की बच्ची की हो गई मौत, कुएं का पानी पीने के कारण संक्रमण की आशंका

- पिछले साल के बाद केरल में हाल में ही सामने हैं इस प्रकार के तीन मामले
- कुएं के पानी का मेडिकल टेस्ट होने के बाद उसमें अमीबा की मौजूदगी की हुई पुष्टि

दुनिया में 97%, मगर केरल में 25% है डेथ रेट

- भारत में आज से 54 साल पहले सामने आया था पीएएम का पहला मामला
- गत वर्ष केरल में आए आए थे इस तरह के 36 मामले, नौ लोगों की गई थी जान

46 डिग्री सेल्सियस तापमान विकास के लिए अनुकूल

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मामले कोझिकोड जिले के अलग-अलग गांवों से सामने आए हैं, जिससे इनमें कोई समानता नहीं दिखती। भारत में पीएएम का पहला मामला 1971 में सामने आया था, और केरल में 2016 में पहली बार ये सामने आया। पिछले साल केरल में ऐसे 36 मामले सामने आए और नौ मौतें हुईं। विशेषज्ञों के अनुसार, फाउलेरी अमीबा दुनियाभर में गर्म, मीठे पानी और मिट्टी में पाया जाता है। 46 डिग्री सेल्सियस तक का उच्च तापमान इसके विकास के लिए अनुकूल होता है।

कार्रवाई : रातू रोड बस स्टैंड के पास रांची पुलिस ने मारी रेड

बिहार से आ रही बस से दो करोड़ के नकली नोट बरामद, दो आरोपी धराए

PHOTON NEWS RANCHI : शनिवार को रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने करोड़ों रुपये के नकली नोट बरामद किए। डीआईजी-सह-एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुखदेवनगर इलाके में रेड कर फेक इंडियन करेंसी को पकड़ा गया है। कोतवाली डीएसपी ने बताया कि रातू रोड बस स्टैंड के पास बिहार से आने वाली चंद्रलोक बस की रेकी शुरू की गई। इसी दौरान कार्टन में रखे लगभग दो करोड़ के जाली नोट बस से उतार कर कुछ लोग कार में रखने लगे, जिन्हें मौके से रंगे हाथ पकड़ा गया।

कार्टन से 500 रुपये के 42 बंडल किए गए जब्त

खपाने की थी तैयारी

पुलिस ने जब कार्टन खोला, तो उसमें से 500 रुपये के 42 बंडल मिले। सभी जाली थे। डीएसपी ने बताया कि मौके से मोहम्मद साबिर और साहिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों राजधानी में जाली नोटों का कारोबार करते हैं और इसे खपाने की तैयारी में थे।

दिल्ली का है मास्टरमाइंड

कोतवाली डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली के एक संगठित आपराधिक गिरोह के द्वारा जाली नोट के गिरोह का संचालन किया जाता है। जिसका मुखिया नीरज कुमार चौधरी है जो दिल्ली में रहता है। उसके द्वारा ही फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद साबिर और साहिल कुमार के जरिए नकली नोट ग्राहकों को भेजा जाता है। गिरोह के द्वारा नकली नोटों के बंडल के ऊपर और नीचे एक-एक असली नोट डालकर शेष नकली नोट रख जाता है और इसके बदले ग्राहकों से 40000 से लेकर 50000 लेते थे।

जोधपुर : समय के झरोखों से झांकती धूप

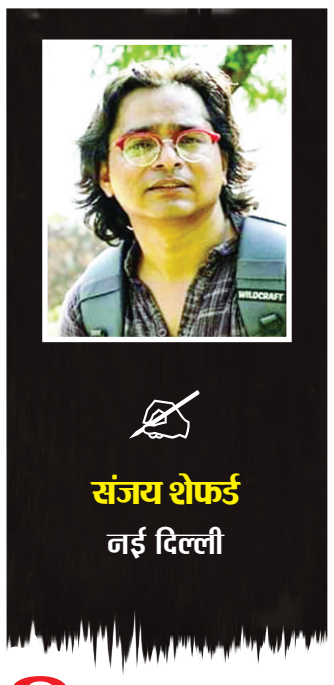

संजय शेफर्ड
नई दिल्ली

घुमक्कड़ की पाती

मेहरानगढ़ किला जैसे किसी इतिहास प्रेमी का सपना हो। किले की दीवारों को छूते ही लगा कि इन पत्थरों ने प्रेम, युद्ध, घृणा और गर्व सभी को सहा है। भीतर की छायाओं में चलते हुए राजाओं के कदमों की गूंज सुनाई देती थी। हर दीवार, हर झरोखा, जैसे कोई कथा कह रही थी। छतरियों के नीचे खड़े होकर जब जोधपुर शहर को देखा, तो नीली छतों का समंदर फैला हुआ था। हर घर जैसे किसी आत्मा की तरह, अदृश्य कहानियां ओढ़े बैठा था। शाम को घंटाघर के बाजार की ओर निकल पड़ा। वह सिर्फ बाजार नहीं था, एक जीवित इतिहास था जो अब भी साँस ले रहा था। मसालों की तीखी गंध, कशीदाकारी के झिलमिलाते थान, ठेठ राजस्थानी बोलियों की खनक और कड़ाही में तलती मिर्ची बड़ी।

संस्कृति में घुला स्वाद

खाना इस शहर की संस्कृति का उत्सव है। सुबह की हल्की धूप में जब गली के नुक्कड़ से मिर्ची-बड़े की खुशबू उठती है, तो भूख केवल शारीरिक नहीं रह जाती। दोपहर की मक्खनिया लस्सी—जिसे एक छोटे से पीतल के गिलास में परोसा जाता है, ठंडक नहीं, प्रेम देती है। शाम के समय, जब शहर की रोशनी धीरे-धीरे पीले रंग में ढलती है, किसी पारंपरिक रसोई में बैठकर दाल बाटी चूरमा खाना, जैसे किसी पुराने गीत को सुनना हो। यहां के भोजन में सिर्फ स्वाद नहीं, एक विरासत होती है। और ठहरने के हर विकल्प में वह आत्मीयता है, जो सिर्फ जोधपुर की मिट्टी दे सकती है। यात्री वहां से केवल थकान मिटा कर नहीं, कुछ आत्मीय लेकर लौटता है, जो उसकी स्मृति में नीले रंग की तरह स्थायी हो जाता है। जोधपुर से लौटते हुए दिल्ली वही थी, चहल-पहल और तेज रफ्तार वाली। लेकिन, भीतर कुछ बदल चुका था। जैसे रेगिस्तान की शांत रेत ने मेरे विचारों को भी शांति दे दी हो, जैसे नीले शहर की दीवारों ने मुझे थोड़ा और इंसान बना दिया हो। अब दिल्ली की भागती सड़कों पर भी मैं जोधपुर के रंग ढूंढता हूं। उस गली की सोंधी खुशबू, उस चाय की मिठास और उस बुजुर्ग की बात 'यह मिट्टी कुछ नहीं भूलती'। शायद यही है यात्रा का सबसे बड़ा प्रतिफल कि हम लौटते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे गए थे।

दिल्ली की हलचल भरी सड़कों से निकलते हुए जब मैंने जोधपुर की ओर रुख किया, तो ऐसा लगा मानो महानगर के कोलाहल को पीछे छोड़ते हुए किसी भूली हुई कथा के पन्नों की ओर बढ़ रहा हूं। ट्रेन की खिड़की से देखती हुई धरती एक उपन्यास की तरह खुल रही थी। कभी हरे खेतों के रूप में, कभी रेतीले विस्तारों की तरह। रास्ते में आते कस्बे और गांव किसी पुराने लोकगीत के मुखड़े जैसे लगे, जिन्हें कभी किसी नानी-दादी ने धीमे सुरों में गुनगुनाया होगा। जोधपुर पहुंचना जैसे किसी रंग से भरी नींद से जागना था। शहर का आकाश सचमुच नीला था। इतना नीला कि जैसे किसी कवि की कल्पना में रंग भर गया हो। स्टेशन से बाहर निकलते ही हवा में रेत की सोंधी महक थी और एक ऐसा आदिम अपनापन, जो सिर्फ रेगिस्तान की भूमि ही दे सकती है। ऑटो वाले की मुस्कान से लेकर होटल वाले के हाथ के बने छाछ तक, हर किसी में आत्मीयता थी। जैसे वे तुम्हें जानते हों, तुम्हारे इंतजार में हों।

मेहरानगढ़ किला जैसे किसी इतिहास प्रेमी का सपना हो। किले की दीवारों को छूते ही लगा कि इन पत्थरों ने प्रेम, युद्ध, घृणा और गर्व सभी को सहा है। भीतर की छायाओं में चलते हुए राजाओं के कदमों की गूंज सुनाई देती थी। हर दीवार, हर झरोखा, जैसे कोई कथा कह रही थी। छतरियों के नीचे खड़े होकर जब जोधपुर शहर को देखा, तो नीली छतों का समंदर फैला हुआ था। हर घर जैसे किसी आत्मा की तरह, अदृश्य कहानियां ओढ़े बैठा था।

शाम को घंटाघर के बाजार की ओर निकल पड़ा। वह सिर्फ बाजार नहीं था, एक जीवित इतिहास था जो अब भी साँस ले रहा था। मसालों की तीखी गंध, कशीदाकारी के झिलमिलाते थान, ठेठ राजस्थानी बोलियों की खनक और कड़ाही में तलती मिर्ची बड़ी। सब कुछ जैसे इंद्रियों का उत्सव बन गया हो। एक चायवाले से बतियाते हुए जाना कि जोधपुर में समय चाय की रफ़्तार से चलता है धीरे, धैर्य से और स्वाद के साथ।

दूसरे दिन मांडोर की तरफ निकल गया, जहां वीरों की छायाएं अब भी हवाओं में तिरती हैं। वहां के उद्यानों में खामोशी भी बात करती है और छतरियों के बीच बैठे-बैठे लगा कि मैं किसी पुरखे की गोद में हूं। एक ऐसी जगह, जहां मृत्यु भी गरिमा में ढल जाती है। वहीं एक स्थानीय बुजुर्ग से मिलना हुआ, जिनकी आंखों में इतिहास का धैर्य और भविष्य की चुप्पी दोनों झलकते थे। उन्होंने रेत को उठाकर कहा, 'यह मिट्टी कुछ नहीं भूलती, बेटा'।

तीसरे दिन सूर्यनगरी के सूरज ने कुछ और ही रूप दिखाया। जसवंत थड़ा और उमेद भवन की भव्यता के बीच जोधपुर का वैभव और सौंदर्य जैसे किसी रियासत की आत्मा में रूपांतरित हो गया था। उमेद भवन महल में भव्यता थी, लेकिन उसमें एक सांस्कृतिक नर्माहट भी थी—जैसे राजा-महाराजा अब भी आंगनों में टहल रहे हों और दीवानखाने में शेरवानी की खुशबू अब भी टिकी हो।

उस दिन की शाम मैंने रेगिस्तान की ओर एक छोटी सी जीप सफारी में बिताई। जैसे-जैसे शहर पीछे छूटता गया, धरती का रंग सुनहरा होता गया। बालू के टीले जैसे किसी कवि की कल्पना में उगे हों। ऊँटों की टापों के बीच बैठकर सूर्यास्त देखना किसी ध्यान जैसी अनुभूति थी। सूरज धीरे-धीरे धरती को चूमता हुआ, जैसे रेत में समा गया हो। जैसे किसी अधूरी प्रेमकथा का अंतिम आलिंगन।

चौथे दिन मैंने खुद को गलियों में खो दिया। ब्रह्मपुरी की नीली गलियां, जैसे किसी चित्रकार की रंग-पट्टी हों। वहां के घरों की दीवारें, वहां खेलते बच्चे, दरवाजों के बाहर बैठी दादी-नानियां, सबने मुझे भीतर से छू लिया। एक लड़के से बातचीत हुई, जिसने मुझे बताया कि वह इतिहास पढ़ता है, क्योंकि उसे अपने शहर की कहानी खुद सुनानी है। मुझे लगा जोधपुर केवल धरोहर नहीं, यह भविष्य भी है—जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है।

पांचवां दिन एक विदाई का दिन था, लेकिन जोधपुर ने विदाई को भी सौंदर्य से भर दिया। सुबह-सुबह छत पर चाय पीते हुए कबूतरों के झुंड को उड़ते देखा और लगा जैसे मेरे भीतर भी कुछ उड़ चला हो। नीले शहर की एक छवि मेरे भीतर बस चुकी थी, जो अब शब्द नहीं, अनुभूति बन चुकी थी। इस पांच दिनों के दौरान मैंने यह भी जाना कि जोधपुर की यात्रा सिर्फ स्थापत्य और इतिहास की नहीं होती, यह स्वाद और आतिथ्य की स्मृतियों से भी गुंथी होती है। जब रेत की भूमि पर सूरज अपना सुनहरा परिधान फैलाता है, तब एक यात्री के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह ठहरने और खाने-पीने की उस आत्मीय व्यवस्था का अनुभव करे, जो इस शहर की आत्मा को छूती है।

यदि मन शाही स्पर्श चाहता हो, तो शहर के हृदय में बसे कुछ पुराने महलों को ही होटलों में बदला गया है। जहां मेहराबों के नीचे नींद आती है और झरोखों से शहर की नीली छतें झांकती हैं। वहां बिस्तर सिर्फ आराम नहीं, इतिहास की छाया होते हैं। वहीं कुछ हवेलीनुमा होमस्टे और पारंपरिक गेस्टहाउस हैं, जिनके आंगनों में चाय की प्याली के साथ कहानियां परोसी जाती हैं। ऐसे ठिकाने यात्रियों को घर जैसा सुकून देते हैं, जहां हर दरवाजा किसी स्मृति की तरह खुलता है और हर खिड़की से कोई कथा झांकती है।

कविता

कुमार बृजेन्द्र
रांची

जलती हुई उमर के लिए

एक सहमे हुए शहर के लिए
एक ठहरे हुए पहर के लिए
गीत लिखता हूँ मैं बहारों के
एक जलती हुई उमर के लिए।

एक खुदा था- अब हैं हजारों खुदा
रात दिन सर झुकाए गुजरे हैं
कौन मस्जिद है, कौन मयखाना
फर्क भी मिट गया नजर के लिए।

उनकी सांसें बिकी जुलूसों में
उनकी आहें टंगी सभाओं में
कह रहे थे जहां तुम्हारा है
और वो मर रहे हैं घर के लिए।

आज मंदिर के पुजारी चुप हैं
भीड़ में मंत्र चले आए हैं
तोड़ दो बंद पड़े दरवाजे
कब से बैठे हैं इस सहर के लिए।

व्यंग्य ■ बर्बरीक

'सैयारा का तैयारा'

दिलीप कुमार

'सो चूँ तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई
देखूं तो एक शख्स भी अपना नहीं हुआ'।

उर्दू के मशहूर शायर जॉन एलिया का यह शेर आजकल बड़ा मुफीद है। ये उन ख़्वातीनों-हजरात पर बहुत फिट बैठ रहा है, जो आजकल मोहब्बत का पैमाना 'सैयारा' फिल्म को मान रहे हैं। सैयारा फिल्म की बिडम्बना यही है कि यह बड़ी दिलफरेब है।

इस फिल्म में युवक-युवतियां (जिन्हें अब जेन'जी भी कहा जाता है) अपने वर्तमान प्रेम के साथ फिल्म देखने जाते हैं और अपने भूतपूर्व प्रेम (एक्स) को याद करके दहाड़ें मारकर रोते हैं। मैं भी अपनी दफ्तरी नीरस और उबाऊ दिनचर्या से ऊबकर कर यह जेन जी, मिलेनियल और अल्फा जेनेरेशन की फिल्म देखने चला गया। पहले मैंने सोचा था कि अकेले देखूंगा। अपनी नीरस, एकरस और तनावपूर्ण जिंदगी को जरा सा बदलूंगा। वीकेंड पर मल्टीप्लेक्स में रंगीन एवं आधुनिक कपड़े पहन कर पॉपकॉर्न खाते हुए और कोल्डड्रिंक पीते हुए सुंदर चेहरों को ताड़ने का सुख लेने को मेरा जी बेकरार था। यह सब फंतासी वाली कल्पनाएं करके मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने जिस तरह के सोशल मीडिया पर फिल्म के वीडियो देखे, यह कि उसमें युवक-युवतियां अपने पूर्व प्रेम को याद करके दहाड़ें मारकर रो रहे थे। उस हिसाब से यदि किसी प्रेम दृश्य को देखकर मैं कमजोर पड़ गया और किसी पुरानी प्रेमिका के विरह में आंसू निकल आए तो मेरी पत्नी मेरी कायदे से खबर लेगी।

सो मैंने इतवार के दिन बीवी से कहा 'आज दोपहर का खाना मैं नहीं खाऊंगा। मुझे बाहर कुछ लोगों से मिलने जाना है। कुछ जरूरी काम है'।

'कहीं नहीं जाना है, किसी से मिलने। पूरे हफ्ते लोगों से मिलते ही तो रहते हो। इतने लोगों से मिल कर कौन सा किला फतह कर लिया है, जो अब सन्डे को भी मेल-मुलाकात जरूरी है। सन्डे को फैमली को टाइम दो'।

पूरे हफ्ते फैमली के लिए ही तो खटता हूँ। आज भी तो घर के सारे काम निपटा दिए हैं मैंने। मुझे कहीं जाना है जरूरी काम है, मैंने मिमियाते हुए अपना बचाव किया। 'कोई जरूरी काम का बहाना नहीं चलेगा। आज हम नई ब्लॉकबस्टर मूवी 'सैयारा' देखने चलेंगे। सुना है ऐसी शानदार मूवी दसियों बरस में एक-आध ही आती है। इस मूवी ने तहलका मचा रखा है। मैं अपने फ्रेंड सर्किल के जितने भी वाट्सएप ग्रुप में हूँ। उन सब लेडीज में ये ट्रेंडिंग मूवी देख ली है और सब अपनी सेल्फी डाल रही हैं। सिर्फ मैं ही बची हूँ। हम नहीं देखेंगे ये मूवी तो हम बैकवर्ड माने जाएंगे। आखिर हम भी मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच के हैं। मैं तो तुम्हारी छुट्टी का वेट कर रही थी। हम आज ही चलेंगे ये मूवी देखने। मैं तो सब काम निपटा कर रेडी हो गई हूँ। अब तुम भी रेडी हो जाओ, पत्नी ने आदेशात्मक स्वर में कहा।

मैं हैरान रह गया कि यह औरत कितना जयादा मेरे जीवन में घुस गई है, इसे कैसे पता चला कि मैं क्या करने वाला हूँ? इसका इतना आतंक है मुझ पर कि जो भी मैं सोचता हूँ, वह भी यह जान जाती है।

मैंने उसे शीशे में उतारने का प्रयत्न करते हुए कहा झ

'ये तो लौंडे-लपाड़ों की फिल्म है। हमारी उम्र हो गई है। हमें क्या देखनी है ये फिल्म'।

'अच्छा तो हर सन्डे को बालों में कलर क्यों लगाते हो। हर बुधवार को सैलून में फेशियल क्यों करवाते हो। जवान दिखने के लिये ही ना? ये टाइट जीन्स और टीशर्ट इसीलिए तो पहनते हो, ताकि जवान दिख सको। यानी ये सब करने के लिए ही तो जवान हो और फिल्म देखने की बात हो तो बूढ़े हो जाओगे। इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों? हमें फिल्म देखनी है, उसमें एक्टिंग नहीं करनी है। और जब उम्र हो चली है तो हेयर कलर-फेशियल छोड़ो, नौकरी से वीआरएस लो और धोती-कुर्ता पहनो और घर बैठ कर हरि का भजन करो' उसने तल्ख स्वर में कहा।

मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसके तंज का मर्म और उसके क्रोध की लिमिट की थाह लेने लग तो उसने मुझसे सधे शब्दों में कहा झ

'मैं तैयार होने जा रही हूँ। आज न सिर्फ हम सैयारा मूवी देखेंगे, बल्कि लंच भी बाहर किसी रेस्टोरेंट में करेंगे' यह कहकर मेरे जवाब का इंतजार किए बिना वह कमरे से निकल गई। मैं समझ गया कि यह सैयारा का तैय्यारा (हवाई जहाज) अब कुछ न कुछ करके ही मानेगा। पत्नी की बात से मैं चिढ़ गया और तय किया कि इसे हर हाल में आज मजा चखाना ही है। यानी कि वह सैयारा देख कर रोई तो मैं इसे खूब ताने दूंगा और वह कुछ दिनों तक बैकफुट पर रहेगी। और अगर यह न रोई तो मैं खूब रोऊंगा, ताकि कई दिनों तक यह उधेड़बुन में रहे कि उसके पति परमेश्वर किसकी याद में रो रहे हैं और न आने किस-किस की याद में रो रहे हैं।

सिनेमाहॉल में हम दोनों पहुंच गए। कुछ जाने-पहचाने लोगों से बातचीत कर-के मैंने ये जाना कि ये लोग भी फिल्म को इंज्वॉय करने नहीं, बल्कि रोने के लिए आए हैं। ये उन दफ़्तरी पुरुषों की कौम थी, जो मेरी रोजी-रोटी और परिवार की परवरिश में अपना लड़कपन कहीं बहुत पीछे छोड़ आयी थी और दिन रात तनाव पाले हुए दफ्तर और गृहस्थी की चक्की में पिस रहे थे। यह दफ़्तरी प्राणी आज रोना चाहता था, जी भर के रोना चाहता था, ताकि बरसों से उसके मन में छिपा दर्द आंसुओं के रास्ते निकल जाए, भले ही पुराने भूले-बिसरे प्यार को याद करके। मैं सोच रहा था कि मैं अच्छा-भला चरित्रवान पुरुष अपनी पत्नी को मिल गया हूँ तो मेरी पत्नी मुझे ग्रांटेड ले रही है, पर मैं भी अब उसे सबक सिखाऊंगा। मैं फिल्म में प्रेम दृश्यों को देखकर सुबक-सुबक कर रोऊंगा, ताकि मेरी पत्नी शंका, ईर्ष्या से जल भुन जाए कि मैं किसी पुरानी प्रेमिका को अब भी इतना याद करता हूँ कि विवाह के इतने वर्षों बाद राजी खुशी पत्नी के साथ रहते हुए बिताने के बावजूद मुझे उस पुरानी प्रेमिका की इतनी शिद्दत से याद आ रही है।

फिल्म शुरू हुई, मैं फिल्म के दर्द को आत्मसात करते हुए रोने को तैयार बैठा हूँ। फिल्म चलती रही मैं देखता रहा, रोने को तैयार था पर कमबख्त फिल्म ही ऐसी थी कि न तो आंसू निकले और न ही कोई दर्द महसूस हुआ। मैंने रोने और फिल्म के प्रेमी युगल के दर्द को महसूस करने की बहुत कोशिश की, मगर दर्द महसूस होने की बजाय मुझे उबासी आ रही थी फिल्म की बोरियत से, फिल्म देखकर मेरे रोने-धोने की तो कोई बात ही नहीं थी। मुझे थोड़ी सी आत्मग्लानि भी महसूस हुई कि मैं किस तरह का नराधम प्राणी हूँ। जरा सी भी सामाजिकता नहीं है मुझमें। बस जरा सा रोना ही तो है ताकि एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य पूरे हो जाएं। इसके अलावा मेरे रोने से सिनेमाहॉल में बैठे मेरे बगल के व्यक्ति को पता भी चल जाए कि उसके बगल में एक भावुक मगर जिम्मेदार नागरिक बैठा है, जो सैयारा फिल्म देखकर सिनेमाहॉल में अपने रोने के कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ है। रोने से एक बोनस और यह मिलता कि पत्नी भी जल-भुन जाती डाह से। पर क्या करूँ आँखें सूख गईं 'ए सैयारा तेरे हाल पे सिनेमाहॉल में न रोना आया'।

इंटरवल होने पर मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। मैंने अपने दर्द के वजह की तफ्तीश की तो पाया कि यह दर्द फिल्म के इमोशन की वजह से नहीं था, बल्कि भूख की वजह से था। मैं अपने दर्द का निवारण करने को निकला तो पीछे से आवाज आई,

'जो कुछ खाने -पीने जा रहे हो मेरे लिए भी लेते आना' पत्नी ने पीछे से टोका।

'सिगरेट पीने की तलब लगी है। उसी का सुट्टा लगाने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए भी एक सिगरेट सुलगा लाऊं क्या' तल्ख लहजे में कहते हुए मैंने उसे घूरा।

उसने मुझे आग्नेय नेत्रों से देखा। कुछ देर तक तो मैंने उससे नजरें मिलाईं, फिर अपना आगा-पीछा, भला-बुरा सोचकर मैंने नजरें फेर ली और सिनेमाहॉल से बाहर निकल आया।

मुझे तनाव हो रहा था, सो मैंने सिगरेट सुलगा ली। तनाव मुझे फिल्म के इमोशन पर नहीं, बल्कि अपने निर्णय से उपजे कोफ्त पर था। कि मैंने यह फिल्म देखने का निर्णय क्यों किया था? इससे भला तो यह था कि सन्डे को घर पर रेस्ट करता और पत्नी से ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनवा कर खाता। इतने पैसे भी खर्च हो गए और छुट्टी के दिन भी आराम बदा नहीं हुआ।

मैंने सिगरेट पीने के बाद कोक और सैंडविच उदरस्थ किया और बीवी के लिए वही दोनों खरीद भी लिया है। मैंने तय किया कि अब पैसे लग गए हैं तो फिल्म पूरी देखूंगा और चल कर इस बात को ताड़ता हूँ कि अगर पत्नी जरा सा रोई या सुबकियां ली तो पूरे साल उसे ताने दूंगा और बदले लूंगा, जिस तरह वह मुझे ताने दिया करती है। और हाँ सिगरेट पत्नी के लिए मैंने नहीं ली है।

1. हमें अपना फीडबैक, सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए दिए गए बार कोड को स्कैन करें या मेल करें।
2. आप हमें अपनी रचनाएं, कविता या आलेख भी भेज सकते हैं। जिसे हम अपने आने वाले अंक पर प्रकाशित करेंगे।

SCAN ME

Email- thephotonnewsjharkhand@gmail.com

मयंक सिंह को अजरबैजान से भारत लाने में इंटरपोल ने की मदद

PHOTON NEWS RANCHI : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल की मदद से झारखंड पुलिस के वांटेड अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील कुमार मीणा को अजरबैजान से भारत वापस लाने में सफलता पाई है। सीबीआई ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। बताया कि सीबीआई की अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू) ने एनसीबी-बाकू के साथ मिलकर सुनील मीणा की भारत वापसी में सहयोग किया है।

सीबीआई ने अनुरोध पर मामले को आगे बढ़ाया : झारखंड पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इस मामले को आगे बढ़ाया और इंटरपोल के माध्यम से 10 अक्टूबर 2024 को सुनील मीणा के खिलाफ एक रेड नोटिस जारी करवाया। रेड नोटिस विश्व भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वांछित अपराधियों की तलाश में मदद करता है। इसके बाद सात जनवरी 2025 को राजनायिक माध्यमों से अजरबैजान के अधिकारियों को प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजा गया।100 से अधिक अपराधियों को विदेश से लाने में मिली मदद सीबीआई इंटरपोल चैनलों के माध्यम से भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। इससे ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभव हो पाता है। बीते कुछ सालों में सीबीआई ने इंटरपोल के साथ मिलकर 100 से ज्यादा वांछित अपराधियों को विदेश से भारत वापस लाने में मदद की है।

22 अगस्त को किया गया भारतीय अधिकारी के हवाले

सीबीआई, नई दिल्ली की ओर से झारखंड एटीएस को पत्राचार कर सूचित करते हुए प्रर्यापण संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। इसके बाद एटीएस की ओर उक्त आरोपी को अजरबैजान गणराज्य से भारत प्रत्यार्पण संबंधी सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई। अजरबैजान की ओर से पुन 04 अगस्त 2025 को पत्राचार कर सूचित किया गया कि 22 अगस्त को आरोपी मयंक सिंह को भारतीय अधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया।

झारखंड पुलिस के इतिहास में यह पहला सफल प्रत्यर्पण : ऋषभ झा

रांची हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद एसपी ऋषभ झा ने कहा, झारखंड पुलिस के इतिहास में यह पहला सफल प्रत्यर्पण है। हमें उम्मीद है कि विदेश में मौजूद बाकी अपराधियों को भी जल्द ही प्रत्यर्पण या निर्वासन के जरिए वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा, यह एक बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय हमारे पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री और राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग को जाता है। एक तरफ जहां मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से लाने के लिए एटीएस टीम अपने मिशन में कामयाब हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के उन तमाम जिलों के थानों में जहां मयंक के खिलाफ मामले दर्ज हैं, उनकी समीक्षा पूरी कर ली गई है। मयंक सिंह को सजा दिलवाने के लिए तमाम तरह के सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिन-जिन थानों में मयंक के खिलाफ केस दर्ज है, उसकी समीक्षा की गई है। इसके अलावा रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह में भी मयंक सिंह के खिलाफ मामले दर्ज हैं।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस भी करेगी पूछताछ

एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार मयंक सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजस्थान में भी मामले दर्ज हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस भी मयंक सिंह से पूछताछ करेगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड एटीएस की ओर से आरोपी मयंक सिंह के विरुद्ध रामगढ़, पतरातु (भदानीनगर) थाना कांड संख्या 175/22 में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करते हुए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को आरोपी मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य में डिटेन (निरुद्ध) किया गया। डिटेन करने के बाद अजरबैजान गणराज्य की ओर से एक्सट्रैडिशन डोजियर की मांग की गई।

BRIEF NEWS

रांची नगर मध्यदेशीय वैश्य विकास समिति ने मनाया वार्षिकोत्सव

RANCHI : रांची नगर मध्यदेशीय वैश्य विकास समिति हलवाई समाज द्वारा बाबा गणिनाथ जी महाराज की 55वीं जयंती पर भव्य वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। सुबह बाबा गणिनाथ मंदिर में मंत्रोच्चारण और वेद मंत्रों के साथ पूजा संपन्न हुई। इसके बाद प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों समाज बंधुओं ने भाग लिया। प्रभात फेरी के पश्चात पुलिस एसोसिएशन गेस्ट हाउस में मुख्य समारोह हुआ, जहां बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता, राधा-कृष्ण सज्जा, महिलाओं की कुर्सी रेस तथा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया।

पूर्व अंचलाधिकारी के निधन पर प्रखंड कार्यालय में हुई शोकसभा

RANCHI : शनिवार को कांके प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में पूर्व अंचलाधिकारी जय कुमार राम के आकस्मिक निधन पर शोकसभा हुई। मौके पर प्रखंड और अंचल के सभी कर्मियों और उपप्रमुख ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि दी।
गौरतलब है कि जय कुमार राम पिछले तीन महीना से लीवर की बीमारी से ग्रसित थे और वे छुट्टी लेकर चेन्नई मे इलाज करा रहे थे। इस बीच उनका तबादला एक अगस्त को कांके अंचल से पलामू जिले के पांकी अंचल मे कर दिया गया था। शुक्रवार शाम को जय कुमार राम का इलाज के दौरान ही चेन्नई में निधन हो गया था। शनिवार को उनकी डेड बॉडी रांची एयरपोर्ट होते हुवे उनके पैतृक आवास हजारीबाग के कटकमसाण्डी गांव के लिए लाया गया। रविवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

बेल की शर्त तोड़ने पर स्कूल संचालक को नहीं मिली जमानत

RANCHI : रएजेसी- 15 अमित शेखर की अदालत ने मकसूद आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 7 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मकसूद आलम इटकी में राइजिंग ग्लोब एकेडमी नामक स्कूल का संचालक है। अदालत के समक्ष दर्ज अभिलेखों के अनुसार, शिकायतकर्ता शबनम की शादी मकसूद आलम से मई 2009 में हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विवाह के तुरंत बाद से ही आरोपी एवं उसके परिजनों ने दहेज की मांग शुरू कर दी और मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दी। बाद में उन्हें घर से निकाल भी दिया गया। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत, पत्नी को सम्मान के साथ साथ रखने की शर्त का उल्लंघन करने के कारण अप्रैल 2020 में रद्द कर दी गई थी। गंभीर आरोपों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने कहा कि इस स्तर पर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।

नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने दी योजना को स्वीकृति

रांची का एयरपोर्ट क्षेत्र महानगरों की तर्ज पर होगा डेवलप, 45.03 करोड़ होंगे खर्च

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची के एयरपोर्ट क्षेत्र को अब महानगरों की तर्ज पर आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने एयरपोर्ट से हिनू चौक के रास्ते बिरसा चौक तक के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण की मंजूरी दे दी है। 45.03 करोड़ की लागत से पांच प्रमुख योजनाओं का कार्य कराया जाएगा। इस योजना की घोषणा नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने की। इसके बाद विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुडको को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र निविदा निकालकर कार्य प्रारंभ करें। यह परियोजना न केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगी बल्कि रांची में आने वाले आगंतुकों को एक सुसज्जित, हरित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध वातावरण प्रदान करेगी।
एयरपोर्ट से हिनू चौक 1.65 किमी तक सड़क को 6 लेन तक विस्तृत किया जाएगा। इसमें सतह नवीनीकरण, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, फुटपाथ, साइक्लिंग पाथ, एलईडी लाइटिंग, फ्लोरिंग पैनल, जनजातीय कला पर आधारित चित्रकारी, पत्थर की कलाकृतियां, तोरण द्वार, पार्क, पार्किंग, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। 10.42 करोड़ सड़क निर्माण और 14.64 करोड़ सौंदर्यीकरण पर खर्च होंगे।

» प्रधान सचिव ने टेंडर निकालकर काम शुरू करने का दिया निर्देश

» सड़कों के किनारे मुहैया कराई जाएंगी जरूरी सुविधाएं

जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक धरोहर

प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि यह परियोजना शहरी नियोजन का हिस्सा है, जिससे रांची आने वाले अतिथियों को राजधानी जैसा अनुभव मिलेगा और शहर का प्रथम प्रभाव सकारात्मक होगा। उन्होंने कहा कि परियोजना में झारखंड की जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। इस योजना से न केवल शहर की सूरत बदलेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार, पर्यटन और सांस्कृतिक आकर्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

बिरसा चौक तक सड़क होगी चौड़ी

हिनू चौक से बिरसा चौक 1.2 किमी तक सड़क का सुदृढ़ीकरण और 6 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही पेवर ब्लॉक, छायादार वृक्ष, डिवाइडर पर हरियाली, फुटपाथ, साइकिल पथ, आकर्षक स्ट्रीट लाइट और शौचालय का निर्माण भी होगा। 7.50 करोड़ सड़क निर्माण और 9.03 करोड़ सौंदर्यीकरण की राशि स्वीकृत हुई है।

कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा होगी अपग्रेड

हिनू चौक का आधुनिकीकरण भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को अपग्रेड करने, खाली स्थानों पर झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों की स्थापना, मौजूदा गोलंबर को 12 मीटर से बढ़ाकर 22 मीटर तक विस्तार, एलईडी व रंग-बिरंगी लाइटिंग और हरियाली के साथ सुंदरीकरण की योजना शामिल है। इसके लिए 3.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सूर्या हांसदा एनकाउंटर के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च

■ जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक किया प्रदर्शन सीबीआई जांच की मांग

PHOTON NEWS RANCHI : गोड्डा के सूर्या हांसदा की संदिग्ध मौत के विरोध में शनिवार को राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने जोरदार आक्रोश मार्च निकाला। यह प्रदर्शन राजभवन तक आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन की शुरूआत जिला स्कूल मैदान से हुई, जहां से सभी लोग जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए राजभवन पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सूर्या हांसदा के फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच, दोषी पुलिस अधिकारियों के तत्काल निलंबन, मृतक के परिजनों को सुरक्षा और मुआवजा के साथ उनके द्वारा संचालित विद्यालय की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाने की मांग की। मौके पर पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, महादेव टोप्पो, सुरेंद्र लिंडा, रितेश उरांव, रवि मुंडा सहित कई प्रमुख आदिवासी नेता मौजूद रहे।

हत्या एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र का हिस्सा : मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने कहा कि हांसदा सदैव आदिवासी अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे और उनकी हत्या एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने प्रशासन और माफिया गठजोड़ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आरती कूजूर संयोजक ट्राई फर्स्ट ने इसे मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी संस्कृति पर सीधा आघात है। केन्द्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के सम्मान और अस्तित्व पर है।

सेवादल कोई साधारण संगठन नहीं, बलिदान की है मिसाल : केशव महतो कमलेश

कांग्रेस सेवादल का प्रशिक्षण शिविर शुरू लोकतंत्र व संविधान बचाने का लिया संकल्प

PHOTON NEWS RANCHI : सेवा, त्याग और बलिदान, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा ही हमारी पहचान के संकल्प के साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को नामकुम बगीचा में दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के वरिष्ठ नेता सतीश पॉल मुंजनी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा दल की कार्यकारी अध्यक्ष ज्योति कुजूर एवं संचालन संजय रावत ने किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सेवा दल कोई साधारण संगठन नहीं, बल्कि बलिदान की मिसाल है। उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस की परंपरा को याद किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते राधाकृष्ण किशोर व अन्य • फोटोन न्यूज

पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब व सामग्री के साथ 5 को किया गिरफ्तार

RANCHI : रांची पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अनगड़ा थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध नकली विदेशी शराब बनाने के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब, उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा को बीते 22 अगस्त को गुप्त सूचना मिली कि अनगड़ा थाना क्षेत्र के राजाडेरा गांव में एक मकान में अवैध रूप से नकली शराब का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन और तुरंत कार्रवाई के लिए एसएसपी डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया।

स्वर्णिम भारत एक्सपो में बाबूलाल मरांडी ने युवाओं को दिलाया राष्ट्र निर्माण का संकल्प

PHOTON NEWS RANCHI : सरला बिरला यूनिवर्सिटी के कला मंडपम हॉल में आयोजित स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 का समापन शनिवार को भव्य समारोह के साथ हुआ। तीन दिवसीय इस आयोजन में झारखंड के 49 स्कूलों, 26 विश्वविद्यालयों और विभिन्न संस्थानों से आए हजारों युवाओं ने भाग लिया। आयोजन का नेतृत्व राज्यसभा सांसद डॉ प्रदीप कुमार वर्मा ने किया। समापन समारोह में झारखंड भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दिलाते हुए कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। जब युवा संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। सांसद आदित्य साहू ने एक्सपो की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन भारत के उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करता है। डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि युवाओं और संस्थानों को एक मंच पर लाकर उन्होंने राष्ट्र निर्माण की दिशा में ठोस पहल की है। तीन दिनों तक चले इस एक्सपो में नवाचार, तकनीक, आत्मनिर्भर भारत और संस्कृति के विभिन्न आयाम देखने को मिले। प्रतिभागियों ने 'मेक इन इंडिया'और 'स्टार्टअप इंडिया' जैसे अभियानों की झलक प्रस्तुत की।

कार्यक्रम को संबोधित करते बाबूलाल मरांडी • फोटोन न्यूज

तबाही केतारी बागान के पास बने पुल पर जिला प्रशासन ने रोका आवागमन

भारी बारिश के करण हटिया डैम से ओवरफ्लो होने लगा पानी

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड की राजधानी रांची में लगातार हो रही भारी बारिश का बड़ा असर दिख रहा है। नदियों और डैम का जलस्तर बढ़ गया है। हटिया डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी फैलने लगा है। डैम से पानी बहते हुए देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। बाद में डैम के फाटक को खोल दिया गया। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। जगन्नाथ मंदिर की ओर जाने वाली सड़क में भी दरार आ गई है। लोगों से इस सड़क पर सावधानी से गुजरने की अपील की गई है। नामकुम-चुटिया रोड स्थित केतारी बागान के पास बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस पुल से भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया है। छोटे वाहनों और पैदल यात्रियों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

■ लोगों को सतर्क रहने की दी गई चेतावनी

■ जगन्नाथ मंदिर की और जाने वाली सड़क में आई दरार

जल-जमाव की स्थिति

इसी तरह डोरंडा क्षेत्र से बहने वाली भूसुर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। रात से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। स्थानीय लोग परेशान हैं और आसपास के निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट पर हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

कुंज विहार में बाढ़ जैसे हालात

राजधानी के अरगोड़ा स्थित कुंज विहार का इलाका भी पानी में डुबा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण पिछले तीन दिनों से इस एरिया में लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। लोग परेशान हैं और मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। इसे लेकर पूर्व पार्षद ने भी नगर निगम के अधिकारियों से गुहार लगाई है।

प्रिज्म होलोग्राफी के एमडी को एसीबी कोर्ट से मिली जमानत

RANCHI : झारखंड शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए गए विधु गुप्ता की जमानत याचिका पर रांची एसीबी की विशेष अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने विधु गुप्ता को जमानत की सुविधा प्रदान करते हुए उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल, एसीबी की टीम ने प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) विधु गुप्ता को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। विधु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। एसीबी ने विधु गुप्ता को 20 मई को दर्ज हुए कांड संख्या 09/25 के तहत गिरफ्तार किया था। यह शराब घोटाले में एसीबी की ओर से की गई आठवीं गिरफ्तारी थी।

रिम्स मेडिकोज का फूटा गुस्सा, गंदगी के लिए प्रबंधन को बताया जिम्मेदार

■ पीजी डॉक्टर की स्थिति अभी भी बनी हुई है नाजुक

■ कैंटीन की चाय पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, आईसीयू में कराया गया था एडमिट

PHOTON NEWS RANCHI : राज्य का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल रिम्स एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही को लेकर विवादों में है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जेडीए) ने आरोप लगाया है कि लगभग एक साल पहले संस्थान प्रशासन से डॉक्टरों के लिए रेस्ट रूम और एक स्वच्छ कैंटीन की मांग की गई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मेडिकोज और डॉक्टरों का कहना है कि प्रशासन इस मांग को लगातार नजरअंदाज करता रहा और अब स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। बता दें कि चाय पीने के बाद पीजी डॉक्टर की तबीयत काफी खराब हो गई थी। जिसे तत्काल आईसीयू में एडमिट कराया गया था। जहां उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। मेडिकोज का आरोप है कि कैंपस में हर तरफ गंदगी और कूड़े-कचरे का अंबार लगा हुआ है। जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। इसके बावजूद रिम्स प्रशासन सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय केवल अनावश्यक नियम और स्टूडेंट्स पर कार्रवाई में व्यस्त है। उनका कहना है कि प्रशासन सिर्फ ₹मनी मिल्किंग₹ तक सीमित रह गया है और छात्र कल्याण की अनदेखी हो रही है। जेडीए का कहना है कि रिम्स प्रशासन में जो लोग स्टूडेंट वेलफेयर और हॉस्टल प्रबंधन संभाल रहे हैं,

BRIEF NEWS

लगातार बारिश से गिरा मिट्टी का घर, 50 वर्षीय महिला की मौत

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में ढीपा पंचायत अंतर्गत पटनापोस गांव में लगातार बारिश के कारण मिट्टी का घर गिर गया, जिससे घर में सो रही 50 वर्षीय महिला गुरुवारी टोपनो की मलबे में दबकर मौत हो गई। वह दलकी के माहुलडीहा गांव की रहने वाली थी। कुछ दिन पहले अपने मायके पटनापोस आई थी। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।

कल विस के समक्ष धरना देंगे आरटीआई कार्यकर्ता

JAMSHEDPUR : आरटीआई कार्यकर्ता संघ, केंद्रीय समिति की बैठक शनिवार को हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि 25 अगस्त को झारखंड विधानसभा के समक्ष (कुटे मैदान) में एकदिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। इसमें मुख्य मांग आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय महासचिव कृतिवास मंडल को फोन पर धमकी देने वालों को अविलंब गिरफ्तार करने और आरटीआई कार्यकर्ता सुनील मुर्मू को धमकी देने वाले मुखिया पर कानूनी कार्रवाई शामिल है। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर, उपाध्यक्ष सदन कुमार ठाकुर व दिनेश कुमार कीनू, महासचिव कृतिवास मंडल, सचिव दिनेश कर्मकार आदि शामिल थे।

सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता अरेस्ट

JAMTARA : सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में करमाटांड़ के भाजपा प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र मंडल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंडल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह एवं दुमका सांसद नलिन सोरेन के खिलाफ अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर स्थानीय पार्टी कार्यकताओं ने कड़ी नाराजगी जताते हुए थाने में लिखित शिकायत की थी। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी अभय कुमार ने त्वरित कार्रवाई की और राजेंद्र मंडल को हिरासत में लेकर थाने लाए।

दिशोम गुरु व रामदास सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि

GHATSILA : पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में शनिवार को राज्य के पूर्व सीएम दिशोम गुरु शिबू सोरेन व पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। डाक बंगला रोड स्थित नेताजी नगर भवन में पूर्व सांसद सुमन महतो, बहरागोड़ा विधायक समीर महंती, पोटका विधायक संजीव सरदार, ईचागढ़ विधायक सबिता महतो, पूर्व विधायक सह झामुमो के प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी आदि भी उपस्थित थे। विभिन्न प्रखंडों के झामुमो अध्यक्ष व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दोनों महान हस्तियों के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया।

मेडिकल छात्र की आत्महत्या मामले में छात्रों ने किया हंगामा

स्टूडेंट सेक्शन व बस इंचार्ज को हटाने की मांग को लेकर घंटों चला गेट जाम

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : सिदगोड़ा स्थित मणिपाल-टाटा मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर के छात्र दिव्यांशु की आत्महत्या को लेकर शनिवार को छात्रों ने हंगामा किया। स्टूडेंट्स ने गेट जाम कर दिया। उनकी मांग है कि मणिपाल-टाटा मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट सेक्शन के इंचार्ज डॉ. विनय और बस इंचार्ज सुमित झा को हटाया जाए। स्टूडेंट का कहना है कि दिव्यांशु पांडेय की मौत का जिम्मेदार प्रबंधन है। लेकिन, इन दो अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी है। छात्र बताते हैं कि जब दिव्यांशु ने कुछ खा लिया था और वह छटपटा रहा था तो प्रबंधन के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। डॉ. विनय को इसकी जानकारी मिली तो वे घटनास्थल छोड़कर कहीं चले गए थे। बस इंचार्ज से एंबुलेंस मांगने को कहा गया तो उन्होंने बहाना बनाया कि अभी ड्राइवर नहीं है। स्टूडेंट का कहना है कि जब भी छात्रों को एंबुलेंस की जरूरत होती है तो कह दिया जाता है की एंबुलेंस में डीजल नहीं है। कभी बहाना बना दिया जाता है कि डॉक्टर नहीं है, जिससे स्टूडेंट्स काफी नाराज है। मेडिकल छात्रों का कहना है कि अगर प्रबंधन गुरुवार रात को घटना वाले दिन तेजी दिखाता तो दिव्यांशु की जान बच सकती थी। मगर, प्रबंधन से जुड़े अधिकारी घटना स्थल से हट गए थे। छात्र इस बात से भी नाराज हैं कि प्रबंधन प्रचार कर रहा है कि दिव्यांशु को एंबुलेंस से टीएमएच ले जाया गया। छात्रों का कहना है कि दिव्यांशु को निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया था। यही नहीं, छात्रों का आरोप है कि बस इंचार्ज सुमित झा अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं। छात्रों का आरेप है कि दिव्यांशु लगभग 45 मिनट तक घटनास्थल पर तड़पता रहा मगर, मणिपाल-टाटा मेडिकल कॉलेज के किसी जिम्मेदार की मानवीय संवेदना नहीं जागी कि उसे फौरन अस्पताल पहुंचाए। छात्रों का कहना है कि वह अपने आंदोलन से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रबंधन सजग हो जाए और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो।

मणिपाल-टाटा मेडिकल कॉलेज का गेट जाम करते स्टूडेंट्स ● फोटोन न्यूज

डूबा ओल्ड पुरुलिया रोड का जाबिर पुल, कई अपार्टमेंटों में भरा पानी, खुली निकायों की पोल

स्वर्णरेखा व खरकई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर

PHOTON NEWS RANCHI : पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शनिवार को जिले की प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा और खरकई उफान पर हैं और दोनों का जलस्तर जमशेदपुर में खतरे के निशान को पार कर गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट रूप से लोगों को हिदायत दी है कि वे किसी भी स्थिति में नदी के किनारे न जाएं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया गया है और राहत तथा बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। शुक्रवार की रात से शनिवार सुबह तक हुई भारी बारिश ने नगर निकायों की पोल खोल दी है। पिछले महीने जल भराव के बाद भी मानगो में नालों की सफाई नहीं कराई गई। इस वजह से रात की बारिश में नाले ओवरफ्लो हो गए और इसकी वजह से कई अपार्टमेंटों में पानी भर गया। लोग परेशान हैं मगर, मानगो नगर निगम किसी की एक नहीं सुन रहा है। वह प्रभावशाली नेताओं के कहने पर ही काम कर रहा है। आम जनता त्राहिमाम कर रही है।

मानगो में स्वर्णरेखा नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर

बाढ़ से डूबा मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड का जाबिर पुल

यह है नदियों का जल स्तर

स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर आमतौर पर मानगो पुल के पास 121.50 मीटर पर खतरे के निशान को पार करता है, जबकि शनिवार शाम को यह बढ़कर 122.48 मीटर तक पहुंच गया। खरकई नदी का सामान्य खतरे का स्तर आदित्यपुर पुल पर 129 मीटर है, पर शनिवार शाम 4 बजे आदित्यपुर पुल के पास इसका जलस्तर 131.60 मीटर दर्ज किया गया।

प्रशासन करा रहा माइकिंग

इस बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। निचले क्षेत्रों में लाउडस्पीकर और मुनादी के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। विशेष रूप से जमशेदपुर और आस-पास के क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकारी निदेशों का पालन करें।

NEWS BOX

फुसरो में तेज रफ्तार ट्रक ने चार भैंसों को कुचला, छह घंटे तक मेन रोड जाम

PHOTON NEWS BOKARO : बोकारो जिला के बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत फुसरो-कथारा मुख्य मार्ग के करगली तीन नंबर हीरक रोड के समीप एक ट्रक ने चार मवेशियों को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही सभी की मौत हो गई। घटना के विरोध में भारी संख्या में लोग जुटे और मुख्य मार्ग को जाम करते हुए भारी वाहनों का परिचालन ठप कर दिया। सूचना पर बेरमो थाना प्रभारी रोहित सिंह व नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सत्येंद्र यादव पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। भैंसों के मालिक पंकज यादव ने बताया कि बारिश के कारण खटाल में कीचड़ हो गया है, जिसके कारण भैंसों को सड़क किनारे शेड पर रखा था। वहां से लाने के क्रम में ट्रक ने चपेट में ले लिया और घटना के बाद ट्रक लेकर चालक फरार हो गया। लगभग छह घंटे बाद शाम को सड़क जाम हटाया गया। इस दौरान वाहनों की लंबी लाइन लग गई। घटना की जानकारी पाकर पशु विभाग की चिकित्सक डॉ. सुजाता मुखर्जी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृत मवेशियों की फोटोग्राफी कराई। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने की पहल की जाएगी। वहीं जाम में फंसे वाहन चालकों ने भी मवेशी पालकों से अपील की वे खुले में अपने मवेशियों को सड़कों पर न छोड़ें।

आईफोन की राशि जमा करने के बाद भी नहीं मिला मोबाइल

PHOTON NEWS CHAIBASA : उपभोक्ता से पूरी राशि लेने के बावजूद मोबाइल फोन नहीं देने पर जिला उपभोक्ता आयोग, चाईबासा ने जियो स्टोर, नीमडीह को कड़ा झटका दिया है। आयोग ने जियो स्टोर को ग्राहक की जमा राशि 64 हजार 900 लौटाने और 30 हजार रुपये अतिरिक्त हजार्ने के रूप में देने का आदेश सुनाया है। यह मामला तांतनगर थाना क्षेत्र के गीतीलादेर निवासी दशरथ गोप से जुड़ा है। उन्होंने माइ जियो स्टोर, नीमडीह (चाईबासा) से आईफोन 13 (128 जीबी, नीला रंग) खरीदने के लिए एचडीएफसी बैंक, चाईबासा के माध्यम से फाइनेंस कराया था। मोबाइल की पूरी कीमत 64 हजार 900 जियो स्टोर को अग्रिम रूप से भुगतान कर दी गई थी। जियो स्टोर प्रबंधन ने कुछ दिनों में मोबाइल देने का आश्वासन दिया, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद उन्हें फोन उपलब्ध नहीं कराया गया। पहले स्टोर मैनेजर अमित कुमार निषाद और बाद में नए मैनेजर ने भी न तो फोन दिया, न ही भुगतान की गई राशि लौटाई। इससे परेशान होकर दशरथ गोप ने 12 जनवरी 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग, चाईबासा में मामला दर्ज कराया। आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह एवं सदस्य देवश्री चौधरी की पीठ ने 23 अगस्त को फैसला सुनाया।

- जियो स्टोर पर 30 हजार रुपये जुर्माना
- मोबाइल की मूल राशि 64 हजार 900 रुपये भी लौटाने का दिया उपभोक्ता आयोग ने आदेश

चाईबासा में बीमा कंपनी को मूल दावा राशि के अलावा 35 हजार जुर्माना देने का आदेश

PHOTON NEWS CHAIBASA : जिला उपभोक्ता आयोग, चाईबासा ने बीमा कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस को उपभोक्ता के दावे को गलत तरीके से खारिज करने पर कड़ा झटका दिया है। आयोग ने कंपनी को 70 हजार रुपये की मूल दावा राशि के साथ 35 हजार रुपये का अतिरिक्त हर्जाना और मुकदमा खर्च चुकाने का आदेश दिया है। चाईबासा के छोटा नीमडीह निवासी अतुल कुमार ने वर्ष 2020 में केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अपने परिवार (पत्नी और पुत्री सहित) का स्वास्थ्य बीमा कराया था। उन्होंने नियमित प्रीमियम का भुगतान किया। वर्ष 2023 में उनकी पत्नी रूपा कुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। पहले चाईबासा के एक क्लिनिक में इलाज कराया गया, फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए जमशेदपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। इलाज पर कुल 70 हजार रुपये खर्च हुए। इलाज के बाद अतुल कुमार ने बीमा कंपनी से दावा किया, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि रोगी ने पूर्व से मौजूद बीमारी की जानकारी छिपाई थी। इसके खिलाफ अतुल कुमार ने 11 मई 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग, चाईबासा में मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को दोषी माना।

फेनोम इंडिया-सीएसआईआर हेल्थ कोहोर्ट नॉलेजबेस का उद्घाटन

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR: बमार्माइंस स्थित सीएसआईआर-एनएमएल (नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी) ने फेनोम इंडिया-सीएसआईआर हेल्थ कोहोर्ट नॉलेजबेस (पीआई-चेक) के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। यह एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय जनसंख्या के लिए प्रेसिजन मेडिसिन और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर 23 से 28 अगस्त, 2025 तक स्वास्थ्य जांच शिविर लगेगा। उद्घाटन समारोह सीएसआईआर-एनएमएल की एग्रिको स्थित आवासीय परिसर में हुआ, जिसका उद्घाटन एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधुरी ने किया। डॉ. चौधुरी ने बताया कि इसमें यह मधुमेह, मोटापा और फैटी लिवर रोग जैसी बढ़ती कार्डियो-मेटाबॉलिक बीमारियों के संदर्भ में है।

टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को मिलेगा 12.3% बोनस, अधिकतम 75,223 रुपये

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच शनिवार को हुए समझौते के तहत इस वर्ष कर्मचारियों को 12.3 प्रतिशत बोनस दिया जाएगा। बोनस की अधिकतम राशि 75,223 और औसत राशि 50,160 होगी। बोनस की राशि सात हजार कर्मचारियों को एक सितंबर को उनके वेतन के साथ मिल जाएगी। इसके अलावा 148 अप्रेंटिस को स्थायी किया जाएगा। इनकी एक हफ्ते बाद मेडिकल जांच शुरू कर दी जाएगी। इन सभी को अर्का जैन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा कराया जाएगा। इसके बाद अगर ये कर्मी बीटेक या एमबीए करना चाहते हैं, तो काम करते हुए यह दोनों डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। अस्थायी कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस मिलेगा। बोनस समझौते के साथ ही यह भी तय किया गया कि अगली बार 325 बाई सिक्स कर्मचारियों की स्थायीकरण सूची निकाली जाएगी। पहले यह संख्या 225 तय थी, लेकिन समझौते के दौरान 150 अतिरिक्त कर्मियों को शामिल करने पर सहमति बनी। ज्ञात हो कि 25 जनवरी 2024 को रांची में श्रमायुक्त संजीव कुमार बेसरा और उप श्रमायुक्त राकेश प्रसाद की उपस्थिति में हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत तीन वर्षों में 2700 बाईसिक्स कर्मचारियों को स्थायी करने पर सहमति बनी थी।

क्राइम कोलकाता के बिधान नगर थाने में बंधन बैंक के पांच अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस

बंधन बैंक का अधिकारी शुभम 2.5 करोड़ की साइबर ठगी में गिरफ्तार

PHOTON NEWS JAMTARA/ KOLKATA : जामताड़ा के बंधन बैंक का अधिकारी शुभम कुमार 2.5 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी मामलों में शामिल था। शुभम समेत झारखंड के अलग-अलग जिलों के बंधन बैंक से जुड़े पांच बैंक अधिकारी इसमें शामिल थे। शुभम कुमार समेत इन पांचों के खिलाफ कोलकाता के बिधान नगर साइबर थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोलकाता की साइबर पुलिस ने 11 अगस्त को शुभम को जामताड़ा से ट्रांजिट रिमांड पर लिया और जब सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू हुई तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। पश्चिम बंगाल की साइबर अपराध शाखा ने कोलकाता स्थित निजी क्षेत्र के बंधन बैंक के पांच वरिष्ठ अधिकारियों को ग्राहकों की जानकारी भारी रकम के बदले साइबर ठगों को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शनिवार को पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। साइबर अपराध शाखा को 2.5 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी की जांच में अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में पता चला। गिरफ्तार किए गए लोगों में झारखंड की हजारीबाग शाखा के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ), जामताड़ा शाखा के सीआरओ, धनबाद की सरायढेला शाखा के सेल्स मैनेजर, कोलकाता की मेटियाबुर्ज शाखा के सीआरओ और सेल्स मैनेजर शामिल हैं। 23 जुलाई को बंधन बैंक की ओर से कोलकाता के बिधाननगर थाने में साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जामताड़ा के एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि 11 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने जामताड़ा पुलिस के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस आरोपी बैंक अधिकारी को अपने साथ रिमांड पर कोलकाता ले गई।

- कैश लेकर ग्राहकों की जानकारी जालसाजों को मुहैया कराने के आरोप में बंधन बैंक के पांच वरिष्ठ अधिकारी हुए अरेस्ट
- कोर बैंकिंग सिस्टम व ग्राहकों से गुप्त जानकारी इकट्ठा कर साइबर अपराधियों को बेचते थे

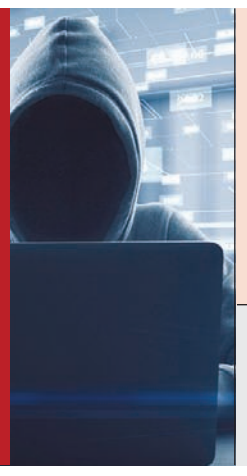

ग्राहकों को बीमा पालिसी व फिक्स्ड डिपोजिट की बात कह लेता था डिटेल

पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोग कोर बैंकिंग सिस्टम से जानकारी इकट्ठा कर साइबर ठगों को मुहैया कराते थे। इसके अलावा ये ग्राहकों को वाट्सएप, एसएमएस या कॉल करके उनकी केवाईसी अधूरी बताकर और जानकारी मांगते थे। ग्राहकों को फिक्स्ड डिपाजिट व बीमा पालिसी का लालच दिया जाता था। इस तरह से उन्होंने कई ग्राहकों की गुप्त जानकारी एकत्रित की। साइबर अपराध शाखा को जांच के दौरान एक के बाद एक सनसनीखेज जानकारी मिली। उसके आधार पर शुक्रवार को अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया।

काम सुरक्षा देने का, बन गया ठग

बैंक के सीआरओ का मुख्य काम बैंक को वित्तीय, परिचालन, प्रतिष्ठा और नियामक संबंधी जोखिमों से बचाना है। वे जोखिमों की पहचान करते हैं, उनका आकलन करते हैं और उन्हें कम करने के लिए रणनीतियां बनाते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक लागू नियमों का पालन करे।

नाबालिग से छेड़खानी का पकड़ा गया मुख्य आरोपी, अन्य की तलाश जारी

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : बागबेड़ा थाना क्षेत्र के प्रधानटोला में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और चोरी की वारदात सामने आई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सागर ओमंग को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी सागर बागबेड़ा के लाल बिल्डिंग स्थित पोस्तो नगर का रहने वाला है। घटना 29 जुलाई को दोपहर करीब 1.50 बजे की है। उस समय किशोरी घर पर अकेली थी। आरोप है कि सागर अपने परिवार के साथ घर में घुस गया और पहले लड़की से छेड़खानी की। इसके बाद घर में रखे जेवर और रुपये लेकर फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने 22 अगस्त को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच के बाद सागर ओमंग को गिरफ्तार किया। मामले में सागर समेत उसकी मां, पिता और बहन को भी आरोपी बनाया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि चूंकि यह नाबालिग से जुड़ा मामला है, इसलिए केस को प्राथमिकता दी जा रही है।

ड्यूटी से लौटे जवान की गला दबाकर हत्या, तीन दिनों तक जंगल में पड़ा रहा शव

PALAMU : पलामू ज़िले में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के सतबरवा बोहित्ता के तीन मुहान की झाड़ी से तीन दिन पहले बरामद हुए शव की पहचान पुलिस जवान विजय उरांव के रूप में हुई है। वे सदर थाना क्षेत्र के चियांकी के रहने वाले थे और फिलहाल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुसाबनी (पूर्वी सिंहभूम) में प्रशिक्षण ले रहे थे। उनकी पहली ड्यूटी देवघर श्रावणी मेला में लगी थी। परिजनों के मुताबिक, मेला ड्यूटी खत्म होने के बाद से ही विजय का कोई अता-पता नहीं चल रहा था। पत्नी ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें केवल इंतजार मिला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अपराधियों ने विजय का गला दबाकर और पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या की।

BRIEF NEWS

कटिहार में हीरो मेंस एशिया कप 2025 की ट्रॉफी का भव्य स्वागत

KATIHAR : कटिहार जिला प्रशासन द्वारा 25 अगस्त को कटिहार खेल भवन में हीरो मेन्स एशिया कप 2025 की ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया जाएगा। यह आयोजन हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में खेल विभाग, बिहार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। हीरो मेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर खेल अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में एशिया की शीर्ष 8 टीमें भाग लेंगी, जिनमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान शामिल हैं। प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर चांद है, जो साहस, स्फूर्ति और कौशल का प्रतीक है। यह शुभंकर भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ पर आधारित है, जो शक्ति और उत्साह का संदेश देता है।

पितरों की तृप्ति व कर्मकांड के लिए कुशी अमावस्या के दिन कुश संग्रह शुरू

SAHARSA : पितृपक्ष के दौरान पितरों की तृप्ति एवं पर्व त्योहार कर्मकांड में शुद्धिकरण के लिए कुश का उपयोग किया जाता है। जो भाद्रपद कृष्ण अमावस्या के लिए उखाड़ा जाता है। शनिवार को विभिन्न वन क्षेत्र एवं जंगल जाकर कुश संग्रह किया जाता है। इस संबंध में शिवनगर ग्रामीण राघव झा, माधव झा, अनिल कुमार झा, अवधेश झा, हलखोरी यादव, नारायण कुमर, अशेसर ठाकुर, हेमचंद्र झा एवं पंडित अशोक कुमार झा ने बताया कि आज कुशी आमावस्या के दिन कुशोत्पाटन किया जा रहा है। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन वर्ष भर के लिए पुरोहित नदी, पोखर, जलाशय आदि से कुशा घास एकत्रित कर घर में रखते हैं। कुशा घास का प्रयोग पूजा-पाठ एवं कर्मकांड कराने में किया जाता है।

बलभद्र पूजा की तैयारी को लेकर हुई बैठक

EAST CHAMPARAN : बलभद्र पूजा की तैयारी को लेकर शनिवार को कलवार सेवा समिति सुगौली की बैठक आयोजन समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कार्यक्रम की सफलता को लेकर आवश्य विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर उपस्थित सदस्यों ने अपना अपना मंतव्य दिया। मौके पर कार्यक्रम का आखिरी रुप - रेखा तय कर आयोजन समिति द्वारा युवा टीम को पुजा कराने का जिम्मेवारी सौंपा गया, जिसके बाद पुजा से संबंधित जानकारी दी गयी। मौके पर कलवार सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, सचिव कुणाल कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष डा.प्रशांत कुमार, सदस्य कामेश्वर गुप्ता, उदय गुप्ता, कुंदन गुप्ता, सुभाष गुप्ता, शशिभूषण गुप्ता, गौरीशंकर प्रसाद, राजा कुमार, प्रियांशु कुमार, संतोष गुप्ता, प्रशुराम गुप्ता, सचिन कुमार आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का किया निरीक्षण, कहा-

आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें अधिकारी

AGENCY PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना के राजेंद्र नगर में लगभग 21 एकड़ में बन रहे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साईंस सिटी का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साइंस सिटी के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साईंस सिटी विज्ञान के प्रचार-प्रसार के विश्व के बेहतरीन केन्द्रों में से एक और अपने आप में विशिष्ट होगा। इस साईंस सिटी के निर्माण को लेकर कई विशेषज्ञों की राय ली गयी है। साईंस सिटी का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां आनेवाले छात्र-छात्राओं को विज्ञान की मूलभूत बातें, गतिविधियों और विज्ञान के सिद्धांतों को सरलता से समझने में सुविधा होगी तथा विज्ञान में उनकी रूचि बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर यहां बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर युवा वर्ग के लड़के-लड़कियों के बीच विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राजेन्द्र नगर, पटना में 21 एकड़ के भूखंड पर साईंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 889 करोड़ रुपये की लागत से साईंस सिटी की स्वीकृति दी गयी हैष इसका निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिस समय इस साईंस सिटी की परिकल्पना की गयी थी, उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस पर सुझाव के लिए महान वैज्ञानिक और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी को भेजा गया था, वे उस समय तक देश के राष्ट्रपति नहीं बने थे। बाद में डॉ. कलाम देश के राष्ट्रपति बने तथा वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री के अनुरोध पर वे बिहार आये तथा विधान मंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया। डॉ. कलाम की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में इस साईंस सिटी का नामाकरण उनके नाम पर किया गया।

साइंस सिटी के निर्माण कार्य की जानकारी लेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य

सीएम ने हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार से 12 साहित्यकारों को किया सम्मानित

PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अंतर्गत राजभाषा के द्वारा आयोजित हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार (2023-24) वितरण समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार (2023-24) के अधीन विभिन्न श्रेणियों के लिये अखिल भारतीय स्तर पर चयनित तथा इस समारोह में उपस्थित 12 साहित्यकारों / संस्थाओं को पुरस्कृत किया। समारोह के दौरान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा-दीक्षा तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में विशिष्ट योगदान के लिये जियालाल आर्य को बाबा साहब अम्बेदकर पुरस्कार प्रदान किया। इसके अन्तर्गत उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 5 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी। सृजनात्मक लेखन के माध्यम से सामाजिक समरसता को निरूपित करने में विशिष्ट योगदान के लिये डॉ. शिव नारायण को बीपी मंडल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 4 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी। उपन्यास, कविता, आलोचना आदि में विशिष्ट योगदान के लिये डॉ. महेन्द्र मधुकर को नागार्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें भी अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 4 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी। आंचलिक कथा लेखन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये हृषीकेश सुलभ को फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अन्तर्गत उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं 4 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि प्रदान की गयी। हिन्दी साहित्य की समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान के लिये वंदना राग को महादेवी वर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया।

चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता पं.राजकुमार शुक्ल को जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि

EAST CHAMPARAN : चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल को उनकी जयंती पर शनिवार को मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी संग्रहालय में स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित राजकुमार शुक्ल जी के कृतित्व व व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए लोगो ने निलहे अंग्रेजो से किसानो को मुक्त कराने के लिए उनके अथक प्रयास को स्मरण करते कहा कि पंडित शुक्ल ने ही बार बार गांधी जी आग्रह कर उन्हे चंपारण बुलाया जिसके बाद चंपारण सत्याग्रह के द्वारा आजादी की नीव रखी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गांधी संग्रहालय के उपाध्यक्ष पत्रकार चंद्रभूषण पांडेय कहा कि चंपारण में निलहे अंग्रेजों द्वारा किसानों पर अत्याचार और क्रूरता बरती जा रही थी, तिनकठिया प्रथा के द्वारा अंग्रेज किसानो का शोषण कर रहे थे।

किसानो के आग्रह पर इस पीड़ा व व्यथा से पं राजकुमार शुक्ल ने ही सर्वप्रथम गांधी जी को अवगत कराया। एक बार नही कई बार वे गांधी जी से मिलकर उन्हे चंपारण आने को विवश किया। शुक्ल जी लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पहुंच कर गांधी जी को चंपारण के किसानो की पीड़ा बताया और चंपारण चलने को कहा। शुक्ल जी के आत्मविश्वास दृढ़ निश्चयी भाव को देखते हुए गांधीजी अंततः चंपारण आने के लिए राजी हो गए। 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुँचे गांधीजी ने किसानों पर हो रहे अत्याचारों की जाँच करना शुरू किया तो घबरायी ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया।

पीएम के बिहार दौरे को लेकर पोस्ट करने पर तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

AGENCY PATNA : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करवाई गई है। यह प्राथमिकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दो नेताओं द्वारा कराई गई है।

उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने सदर बाजार थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि राजद के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को एक पोस्ट जारी किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उनकी फोटो का उपयोग भी किया गया है, जिससे जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

महाराष्ट्र में भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत पर पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धारा जैसे धारा 196(1)(ए)(बी), 356(2)(3), 352, 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गढ़चिरोली के भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत में कहा कि गयाजी में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी की सभा थी। उसी सभा की पृष्ठभूमि में तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कार्टून साझा किया।

'एक्स' पर यह पोस्ट किया गया था जारी

कोसी सीमांचल के प्रवेश द्वार कुर्सेला में नहीं रुके राहुल गांधी व तेजस्वी, मायूस लौटे लोग

AGENCY KATIHAR : वोटर अधिकार यात्रा के तहत शनिवार को कोसी सीमांचल का प्रवेश द्वार माने जाने वाले कटिहार के कुर्सेला में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और सीपीआई (एमएल) नेता दीपांकर भट्टाचार्य का काफिला पहुंचा, लेकिन नेताओं का काफिला बिना रुके आगे निकल गया।

कहने को यह यात्रा सीमांचल की शुरूआत कुसेर्ला से होनी थी, लेकिन नेताओं का काफिला बिना रुके आगे निकल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले से कार्यक्रम था कि कुसेर्ला शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर यात्रा का आगाज होगा। इसी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी और कार्यकर्ताओं ने भी पूरे चौक और स्मारक को सजाया था। बीती रात से ही पोस्टर-बैनर लगाने का काम चल रहा था। सुबह से हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए अपने नेताओं के स्वागत को बेताब थे। लेकिन उम्मीदें उस समय टूट गईं, जब राहुल गांधी अपनी गाड़ी की सीट से बाहर भी नहीं निकले और काफिला सीधे आगे बढ़ गया।

तेजस्वी यादव व अन्य नेता भी मंच या जनता से रूबरू नहीं हुए। हालांकि तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी व दीपांकर भट्टाचार्य अंत में कुछ समय के लिए वैन पर खरे होकर हाथ हिलाते दिखें।

वहीं सड़क किनारे घंटों से इंतजार कर रहे कई लोगों को तो यह तक पता नहीं चला कि राहुल गांधी आए भी थे और निकल भी गए।

वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का काफिला

एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 28 को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लेंगे भाग

AGENCY ARARIA : फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आगामी 28 अगस्त को भद्रेश्वर स्थित मिथिला पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री हरि सहनी,लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वेदप्रकाश पांडेय, मंत्री महेश्वर हजारी,पूर्व सांसद कविता सिंह शिरकत करेगी। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दलों के नेताओं ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और शहरी सहित ग्रामीण इलाकों में बैठक कर अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं के शिरकत करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केशरी उर्फ मंचन केशरी के आवास स्थित जनसंपर्क कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा, जनता दल यूनाइटेड के नौशाद आलम, हम के जिलाध्यक्ष विष्णु देव ऋषिदेव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष विभाष मेहता, विधायक विद्यासागर केशरी उर्फ मंचन केशरी ने नगर के एनडीए कार्यकताओं के साथ मीटिंग की और प्रत्येक बूथ से अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

NEWS BOX

ओम शांति केंद्र के रक्तदान शिविर में एकत्रित हुआ 68 यूनिट रक्त

AGENCY ARARIA : प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा फारबिसगंज के छुआपट्टी स्थित ओम शांति केन्द्र में आयोजित रक्तदान शिविर में 68 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन, मुख्य पार्षद वीणा देवी,डॉ अजय कुमार सिंह, डॉ महेश मानव ठाकुर, डॉ उमेश चन्द्र मंडल, डॉ सुषमा केडिया एवं केन्द्र की संचालिका बी के रुकमा दीदी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। केन्द्र की संचालिका बी के रुकमा दीदी ने अपने संबोधन में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि लायंस क्लब के सहयोग से राजयोगिनी दादी प्रकाशमणिजी के 18 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।उन्होंने कहा कि दादी जी शांति, नम्रता, सरलता, श्रेष्ठ नेतृत्व एवं विश्व बंधुत्व की सजीव प्रतिमूर्ति थी। रक्तदान कार्यक्रम समस्त भारत के अलावा पड़ोसी देश नेपाल, चीन में भी एक साथ आयोजित है, जिसमें एक लाख यूनिट ब्लड का संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदान शिविर में लायंस क्लब का सहयोग सराहनीय रहा।जिसमें लायन्स क्लब के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल,हरीश अग्रवाल, जयकुमार अग्रवाल, आलोक अग्रवाल के अलावा लैब टेक्निशियन राघव कुमार, रईस अंसारी,अमन कुमार, रोबिन सिंह के साथ डॉ शंभू सिंह, रीतेश कुमार पवन कुमार ने सराहनीय सहयोग किया।

जोगबनी से वंदे भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर हुई बैठक

AGENCY ARARIA : वंदे भारत एक्सप्रेस का जोगबनी से संचालन न होकर पूर्णिया से संचालन किए जाने के निर्णय को लेकर नेपाल के विराटनगर में रेल यात्री सहजीकरण समिति की बैठक शनिवार को हुई। जिसकी अध्यक्षता समिति के प्रमुख सलाहकार महेश साह स्वर्णकार ने किया। बैठक में समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि भारतीय रेल यात्रा के लिए एक विशिष्ट पहचान बन चुकी है लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जोगबनी से न चलाकर पूर्णिया से संचालन किए जाने के कारण भारत नेपाल के हजारों रेल यात्री के उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया, जब बिहार के लिए घोषित रेल परियोजनाओं में पटना से सहरसा के रास्ते पूर्णिया तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाने की घोषणा की। इस घोषणा से सीमांचल सहित नेपाल के यात्रियों की अनदेखी होने की बात कही बैठक में जोगबनी से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन की मांग को लेकर रेलमंत्री से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया।

लापरवाही और भ्रष्ट आचरण के आरोप में पांच पुलिसकर्मी निलंबित

AGENCY EAST CHAMPARAN : पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने लापरवाह और भ्रष्ट आचरण वाले पांच पुलिस कर्मियों निलंबित कर दिया है। पुलिस कप्तान ने उक्त कारवाई शराब तस्करों को भगाने,एफआईआर की कॉपी के लिए पैसे मांगने और ड्यूटी से अनुपस्थित रहने जैसे गंभीर आरोपों की जांचोपरांत की है। उन्होने सिकरहना डीएसपी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कुंडवाचैनपुर थाने में प्रतिनियुक्त प्रोबेशनरी ट्रेनिंग कॉन्स्टेबल (पीटीसी) पंकज कुमार और चौकीदार गुंजन कुमार को शराब तस्करों को भगाने के आरोप में निलंबित किया है। वही मोतिहारी नगर थाना में थाना मैनेजर के पद पर कार्यरत महिला सिपाही संगीता कुमारी को नगर थानाध्यक्ष के प्रतिवेदन के आधार पर एक फरियादी से एफआईआर की कॉपी मांगने पर खुद को मुंशी बताते हुए एफआईआर की कॉपी देने के बदले पैसे की मांग करने के आरोप में निलंबित किया है इसके अतिरिक्त,पकड़ीदयाल डीएसपी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर ओडी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर सहायक उप-निरीक्षक सुरेश कुमार निराला (राजेपुर थाना) और पुलिस उप-निरीक्षक मिथिलेश राम (मधुबन थाना) को निलंबित किया है। साथ ही पुलिस कप्तान ने संदर्भित थाना के थानाध्यक्षों से भी स्पष्टीकरण मांगी है।

वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षक ने शुरू किया जनसंपर्क

AGENCY ARARIA : लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर महागठबंधन के दलों के नेता लगातार जिले में जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पर्यवेक्षक एवं अररिया जिला वोटर अधिकार यात्रा के प्रभारी नदीम जावेद ने शनिवार को फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस नेता नदीम जावेद ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में रविवार को होने वाले वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने की अपील की। फारबिसगंज के दरभंगिया टोला वार्ड संख्या 12 में कांग्रेस नेता नदीम जावेद ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। मौके पर नदीम जावेद ने कहा कि वोट चोरी कर सत्ता में आई भाजपा सरकार लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। वहीं बिहार में नीतीश सरकार मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर लोगों को काफी परेशान कर रही है। जीवित लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा वोटरों के अधिकार के लिए वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। जनसंपर्क के दौरान पार्षद एवं एनएसयूआई जिलाध्यक्ष इरशाद सिद्दीकी, सद्दाम प्रधान, मुमताज सलाम, शाकिर हुसैन, अनीश आलम, गौरव कुमार, मासूम अंजार, शाहजहां शाद, सन्नी खान, मेहराब, बबलू सिद्दीकी अमन राजा आदि साथ रहे।

समस्या छत से लगातार टपकता है पानी, दीवारों में सीलन और पड़ चुकी हैं गहरी दरारें

जर्जर भवन और संसाधनों की कमी के बीच पढ़ाई कर रहे बच्चे

AGENCY BHAGALPUR : जिले के नाथनगर प्रखंड के बरारीपुर मास्कन मध्य विद्यालय का भवन बेहद जर्जर हो चुका है। भवन इस हालत में पहुंच गया है कि किसी भी वक्त उसके ढहने का खतरा बना हुआ है।

छत से लगातार पानी टपकता है, दीवारों में सीलन और गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। कई जगह मलवा टूटकर गिर रहा है और कमरों की हालत भूतिया हवेली जैसी प्रतीत होती है। पंखा-लाइट तक चोरी हो जाते हैं। विद्यालय में न तो पंखे हैं और न ही प्रकाश की उचित व्यवस्था। जो भी विद्युत व्यवस्था लगाई जाती है, वह चोरी की भेंट चढ़ जाती है। यहां तक कि चोर तार तक उखाड़ ले जाते हैं। विद्यालय परिसर में खिड़की और दरवाजे तक नहीं बचे हैं। बाउंड्री वॉल पार करके असामाजिक तत्व और नशाखोर स्कूल में घुस जाते हैं और यहां नशा करते हैं। इस कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल 141 बच्चों का नामांकन है। जिसमें औसतन 100 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं। मगर इतनी बड़ी संख्या के बच्चों के लिए शिक्षकों की भारी कमी है। विद्यालय में कुल तीन शिक्षक पदस्थापित हैं, जिनमें से एक महिला शिक्षिका निर्लंबित हैं। प्रधानाध्यापक प्रीतम कुमार चुनाव आयोग के कार्य में व्यस्त हैं। नतीजतन, पूरे विद्यालय का भार एकमात्र शिक्षक पर आ चुका है। शिक्षक अभिषेक कुमार ने बताया कि बच्चों को जर्जर कमरों में पढ़ाना जोखिम भरा है, इसलिए मजबूरी में उन्हें बरामदे में बैठाकर पढ़ाया जाता है, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। विद्यालय भवन की मरम्मत और शिक्षक की नियुक्ति को लेकर शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी और बीआरसी कार्यालय को कई बार आवेदन दे चुके हैं। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब सिर्फ प्राइमरी स्तर तक शिक्षा कभी यहां कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन पास में गुरुकुल हाई स्कूल खुलने के बाद इसे महज प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) तक सीमित कर दिया गया। बदहाल हालातों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जर्जर भवन, शिक्षकों की कमी और सुरक्षा संकट के साए में छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

जर्जर भवन में जमीन पर बैठकर पढ़ते बच्चे

महावीरी शोभायात्रा में विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

AGENCY ARARIA : फारबिसगंज में रामायण परिषद की गठन और सांवलिया कुंज ठाकुरबाड़ी में प्रतिमा स्थापना को लेकर 1904 से निकलने वाला महावीरी शोभायात्रा रविवार को निकलेगी। महावीरी शोभायात्रा सांवलिया कुंज ठाकुरबाड़ी से निकलकर पूरे शहर का परिक्रमा कर पुनः मंदिर परिसर में आकर समाप्त होता है। जुलूस ने शहरी क्षेत्रों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों के अखाड़ों के लोग पारंपरिक लाठी डंडा और भगवा ध्वज के साथ भाग लेते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं इस शोभायात्रा जुलूस में भागीदारी होती है। जुलूस में विधि व्यवस्था संधारण जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। महावीरी झंडा शोभायात्रा जुलूस के शांतिपूर्ण ढंग से निकलने और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर डीएम अनिल कुमार,एसपी अंजनी कुमार के नेतृत्व में शनिवार को फारबिसगंज थाना से पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। जिसमें फारबिसगंज एसडीएम रंजीत कुमार रंजन, डीएसपी हेडक्वार्टर फखरे आलम, फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, डीसीएलआर अमित कुमार समेत कई थाना की थानाध्यक्ष, पुलिस अधिकारी और बलों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

चार दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, परिजनों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप

DARBHANGA : जिले में सकतपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में गर्भवती विवाहिता चंदा देवी की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। घटना के चार दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। पुलिस ने अबतक पूछताछ के लिए हिरासत में ली गई दो महिलाओं को जेल भेज दिया है, लेकिन अन्य आरोपित फरार हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने आरोपितों के घरों की तलाशी तक नहीं ली और न ही मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया गया। हत्या में उपयोग किए गए हथियार या यदि जहर देकर मारा गया तो उसकी शीशी-पुर्जा जैसे साक्ष्य भी अबतक नहीं मिले हैं।

शिक्षा में इतिहास या राजनीति की कवायद

भारत पर शासन के दौरान 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का पहला विभाजन किया तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वही बीज एक दिन पाकिस्तान के रूप में धरती के मानचित्र पर अंकित होगा। यह औपनिवेशिक सत्ता की बांटो और राज करो की नीति का परिणाम था। इस नीति ने धीरे-धीरे पूरे उपमहाद्वीप को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की राह तैयारी की। विडंबना यह है कि 21वीं सदी में भी उसी नीति को अलग-अलग तरीकों से भुनाने की कोशिश की जा रही है। एनसीईआरटी का विशेष माड्यूल विभाजन की त्रासदी इसी प्रवृत्ति की एक कड़ी प्रतीत होता है। इसमें जिन्ना और माउंटबेटन के साथ-साथ कांग्रेस को भी भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया गया है। इसे समझना कठिन है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और इससे किसके हित सधेंगे। यह सच है कि विभाजन भारतीय इतिहास की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक था। भारत विभाजन में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए और सामाजिक ताने-बाने को गहरी चोट पहुंची। इसी के साथ यह भी उतना ही सच है कि भारत के दुर्भाग्यपूर्ण और त्रासदी विभाजन का कारण केवल कुछ नेताओं के व्यक्तिगत निर्णय नहीं थे, बल्कि दशकों से पनप रही औपनिवेशिक नीतियां, सांप्रदायिक राजनीति और लंबे समय से चले आ रहे किस्म-किस्म के सामाजिक तनाव का नतीजा थे। ऐसे जटिल ऐतिहासिक प्रसंगों का खतरनाक ढंग से सरलीकरण करके जिन्ना और माउंटबेटन के साथ कांग्रेस के माथे पर ठीकरा फोड़ना न केवल अन्याय है, बल्कि इतिहास को वर्तमान की राजनीति के हिसाब से मोड़ने का दुस्साहस भी है। इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। इतिहास वैसा ही पेश किया जाना चाहिए, जैसा घटिल हुआ हो। इतिहास का मतलब ही है कि ऐसा हुआ था। यह एक वास्तविकता है कि कांग्रेस ने विभाजन की मांग कभी नहीं की। उसने तो विभाजन का विरोध किया और उसे रोकने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए। भारत विभाजन तो मुस्लिम लीग और जिन्ना का एजेंडा था। अंग्रेजों ने भी इसे प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत को कमजोर कर के यहां लंबे समय तक शासन करना था। इसके अलावा वे भारत का विभाजन इसलिए भी करना चाहते थे, ताकि उससे अलग होकर बने देश यानी पाकिस्तान में अपनी चला सकें। 1909 के चुनावों में अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हो या 1932 का कम्युनल अवार्ड, हर कदम पर ब्रिटिश शासन ने हिंदूमुस्लिम एकता को चोट पहुंचाने का काम किया। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के रिश्तों में दरार डालने के काम करते ही रहते थे, ताकि उन्हें भारत पर शासन करने में आसानी हो। कांग्रेस लगातार राष्ट्रीय एकता की बात करती रही, लेकिन जब 1940 के दशक में सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंच गया, तब उसके पास समझौते के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचा। अच्छा होता कि आज लोग उस समय की परिस्थितियों को समझें। कहा भी जाता है कि देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से चलना चाहिए। इस बात को सदैव ध्यान में रखा जाए तो अच्छा कि 1946-47 का भारत आज के लोकतांत्रिक और भारत से बिल्कुल अलग था। उस समय 500 से अधिक रियासतें थीं, जिनकी अपनी-अपनी आकांक्षाएं और सोच थी। बंगाल, पंजाब और बिहार में भयंकर दंगे भड़क चुके थे। सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ चुका था कि हर दिन हजारों निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। ऐसे में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में कांग्रेस के सामने दो ही रास्ते थे- या तो विभाजन स्वीकार कर देश को आगे बढ़ने दें या फिर विभाजन रोकने की कोशिश में पूरे उपमहाद्वीप को खून-खराबे में झोंक दें। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने पहला रास्ता चुना और भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव दी। इसे उन लोगों को समझना चाहिए, जो विभाजन के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराने के लिए तरह-तरह के सुविधाजनक तर्क पेश करते रहते हैं। यह कहना आसान है कि कांग्रेस ने भारत विभाजन को स्वीकार कर गलती की। इसी तरह यह कहना भी भूल होगी कि उस दौर में नेताओं के सामने और कई विकल्प उपलब्ध थे। महात्मा गांधी जैसे नेता भी विभाजन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन जब लाखों लोगों की जान दांव पर लगी थी, तब समझौते को ही व्यावहारिक रास्ता माना गया। कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता पाना नहीं, बल्कि देश को भीषण गृहयुद्ध की आग से बचाना था। आज 79 साल बाद सुरक्षित माहौल में बैठकर विभाजन के दौर की विवशताओं को अनदेखा करना आसान है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यदि उस समय कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार न किया होता तो शायद हालात और भी भयावह होते। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कांग्रेस ने कठिन मगर आवश्यक निर्णय लिया, ताकि भारत का भविष्य बचाया जा सके। एनसीईआरटी का माड्यूल इतिहास की जटिलताओं को सरलीकृत करके वर्तमान की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास है। इस नए माड्यूल को भले ही किसी कक्षा में पाठ के तौर पर न पढ़ाया जाए, लेकिन आखिर इसे पूरक शैक्षिक सामग्री के तौर पर पेश करने और उसमें विभाजन के लिए जिन्ना और माउंटबेटन के साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराने का क्या मतलब। सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, इतिहास बदलने की कोशिश हमेशा अधूरी और संदिग्ध रहती है। वास्तविक इतिहास हमें यही सिखाता है कि भारत का विभाजन औपनिवेशिक नीतियों और जिन्ना की सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम था, न कि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा का। इसलिए यह आवश्यक है कि इतिहास को न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टि से पढ़ाएं। विभाजन के पन्नों से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि उन्हें आज की राजनीति का हथियार बनाना चाहिए। कांग्रेस को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसने उस दौर में देश की एकता और भविष्य की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लिया। इतिहास का मूल्यांकन उसी समय की परिस्थितियों के आलोक में होना चाहिए, न कि आज की राजनीतिक सुविधा के आधार पर।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोक प्रशासन मॉडल

ANALYSIS

✍ डॉ. मयंक चतुर्वेदी

केवल दो वर्षों में 8785 दोषियों को उम्रकैद और 70 को फांसी की सजा सुनाया जाना यह संकेत देता है कि न्यायिक तंत्र के साथ तालमेल बैठाकर अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने में पुलिस की भूमिका कितनी निर्णायक हो सकती है। 1 जुलाई 2023 से अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराना, इनमें माफिया सरगनाओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट के तहत 14,400 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करना केवल आंकड़े नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है कि राज्य में अपराध का कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश का यह मॉडल पारंपरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के ढांचे से आगे बढ़कर एक सक्रिय अपराध निरोधक प्रणाली में विकसित हुआ है। यह केवल अपराध होने के बाद की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपराध के स्रोत, नेटवर्क और आर्थिक जड़ों पर प्रहार करता है। माफिया और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में वित्तीय संपत्ति की जब्ती इस बात का प्रमाण है कि केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके आर्थिक ढांचे को तोड़ना ही असली नियंत्रण है। यही कारण है कि यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन सकता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक ढांचे को स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर समझौता अस्वीकार्य है और इस संदेश का असर पुलिस के हर स्तर पर दिखाई देता है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण में जो प्रयास हुए हैं, वे इस मॉडल के मानवीय पक्ष को भी उजागर करते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध रोकने में तकनीकी पुलिसिंग, सामुदायिक भागीदारी और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को केंद्र में रखकर जो संरचना विकसित की गई है, उसने नागरिकों, विशेषकर महिलाओं में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। यूपी-112 जैसी आपातकालीन सेवा को देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाना और पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर द्वारा 1 जनवरी 2023 से अब तक 1257 आत्महत्या संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर जानें बचाना, इस बात का प्रमाण है कि पुलिस व्यवस्था केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि संवेदनशील हस्तक्षेप और मानवीय सहारे का भी केंद्र हो सकती है। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के उस सिद्धांत के अनुरूप है जिसमें राज्य के सभी अंगों का प्राथमिक उद्देश्य नागरिक कल्याण और मानव गरिमा की रक्षा करना माना गया है। अन्य राज्यों की स्थिति पर दृष्टि डालें तो कई जगहों पर पुलिसिंग अब भी पारंपरिक ढर्रे पर चल रही है। मामले दर्ज करना, वर्षों तक मुकदमे चलना और अपराधियों का जमानत पर बाहर आना आम बात है। कुछ राज्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप और अपराध-राजनीति के गठजोड़ ने पुलिस की कार्यकुशलता को बाधित किया है। ऐसे परिदृश्य में उत्तर प्रदेश का मॉडल एक सकारात्मक दबाव भी बनाता है, क्योंकि नागरिक अब यह देख पा रहे हैं कि सख्त और पारदर्शी पुलिसिंग से अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस मॉडल के व्यापक अनुप्रयोग के लिए अन्य राज्यों को भी अपने कानून-व्यवस्था ढांचे का आधुनिकीकरण करना होगा, तकनीकी क्षमता बढ़ानी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना होगा। वस्तुतः लोक प्रशासन का मूल आधार ही है- कानून का शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही। यदि हर राज्य उत्तर प्रदेश की तरह अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए, तो पूरे देश में कानून व्यवस्था के प्रति नागरिकों का विश्वास कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सख्ती का अर्थ मनमानी नहीं होना चाहिए। संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकार मानकों की रक्षा करते हुए ही कठोर कार्रवाई को लागू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अनुभव से यह सीखा जा सकता है कि सख्ती और संवेदनशीलता का संतुलन कैसे साधा जाए, जहां अपराधी के प्रति कोई नरमी न हो, पर निर्दोष नागरिक की गरिमा और अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। पुलिस कर्मियों के सम्मान और प्रशिक्षण के मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश का उदाहरण उल्लेखनीय है। 60,244 नए कांस्टेबलों को हाइब्रिड मोड में प्रशिक्षित करना, जिसमें साइबर अपराध जांच, एआई टूल्स का उपयोग और सिमुलेशन-आधारित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना शामिल है, यह दिखाता है कि पुलिसिंग अब केवल बल-आधारित नहीं, बल्कि ज्ञान और तकनीक-आधारित पेशा बन चुका है। राष्ट्रपति वीरता पदक से लेकर उत्कृष्ट सेवा पदक तक, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को सम्मानित करना न केवल मनोबल बढ़ाता है, बल्कि पेशेवर ईमानदारी को भी प्रोत्साहित करता है। यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रशिक्षित और प्रेरित बल के कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर यानी 2047 तक वैश्विक मानक की आधुनिक, संवेदनशील और सशक्त पुलिसिंग का लक्ष्य केवल एक नारा नहीं, बल्कि नीति और योजना के रूप में अपनाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर दिया है, जिसे डीजीपी ने मुस्कुराता, आत्मविश्वास से भरा और सुरक्षित नागरिक के रूप में परिभाषित किया। यह लक्ष्य हर राज्य के लिए समान होना चाहिए, क्योंकि नागरिक का आत्मविश्वास ही किसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है। इस मॉडल को देशभर में लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का लोक प्रशासन सुधार मिशन शुरू किया जा सकता है, जिसमें राज्यों को अपने प्रदर्शन और सुधार के आधार पर रैंकिंग दी जाए और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा किया जाए। साथ ही केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को मजबूत किया जाए, ताकि तकनीकी संसाधन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और अपराध-निरोधी रणनीतियां पूरे देश में एक जैसी प्रभावी हो सकें। अंततः कहना यही होगा कि भारत के नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त जीवन देने के लिए अब समय आ गया है कि हर राज्य अपने भीतर के अपराध तंत्र को तोड़ने का साहस दिखाए और एक ऐसे लोक प्रशासन की नींव रखे, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह सख्त, जवाबदेह और संवेदनशील हो।

बांसलोई में बहत्तर ऋतु : उनसठ से चौसठ तक की यात्रा

पुस्तक समीक्षा

✍ डॉ. अविनाश कुमार सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर
हिन्दी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
एवं
संपादक- इस्पातिका

साहित्य जब अपना विषय चुनता है, तो वह जन को केंद्र में रखता है। कई बार यह प्रत्यक्ष होता है और कई बार परोक्ष। लेखन की सभी विधाएं इस नियम का अनुपालन करती हैं, लेकिन जनप्रिय साहित्य वह बन पाता है, जिसकी अवधारणा कालजयी हो यानी वह साहित्य, जो अपने काल में रहते हुए भी भूत और भविष्य में लगभग समान रूप से सार्थक बना रहे। झारखंड के जल, जंगल और जमीन से जुड़े कवि-लेखक सुशील कुमार की नई पुस्तक 'बांसलोई में बहत्तर ऋतु' इस मापदंड पर सर्वथा खरी उतर रही है। पुस्तक के परिचय के रूप में यह बताना बेहद आवश्यक है कि इसका प्रकाशन हिंद युग्म ने किया है। यह पुस्तक सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

पुस्तक के बारे में : यह अपने आप में एक विशिष्ट कृति है। इस पुस्तक के प्रथम खंड में केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मंगलेश डबराल सहित आठ से अधिक समकालीन कवियों की रचनाओं के आलोक में पर्यावरण-संचेतना को सूक्ष्मता से समझने का प्रयास किया गया। दूसरे खंड में कवि-लेखक सुशील कुमार की अपनी

चौसठ पर्यावरण -निबद्ध कविताएं चार सर्गों में शामिल की गई हैं। इनमें पहाड़, जंगल, नदी और तराई में संयोजित हैं। ये कविताएं प्रकृति की पीड़ा, उसके संघर्ष और आशा का सुदीर्घ आख्यान रचती हैं।

पुस्तक का बीज तत्व

पुस्तक के प्रथम खंड की शुरूआत समकालीन कविता में पर्यावरण संचेतना से होती है, जो उनसठ कवियों की पर्यावरणीय कविताओं पर आधारित है। इसकी शुरूआत डीएम मिश्र की गजल से होती है। इसकी पंक्तियां 'रक्त का संचार है पर्यावरण, सांस की रफ्तार है पर्यावरण ...।' समकालीन हिंदी साहित्य और पर्यावरण के बीच के अंतसंबंधों को लेकर शुरू हुई यह यात्रा ऋग्वेद, यजुर्वेद, महोपनिषद, स्कंदपुराण और आदिकाल तक अपनी दृष्टि ले जाती है। इसके बाद भक्तिकाल, रीतिकाल होते हुए आधुनिक काल के धरातल पर पहुंचती है। पुस्तक के पहले खंड में नरेश सक्सेना, बशीर बद्र, दिविक रमेश, रामकुमार कृषक, शंभु बादल, महेंद्र नेह, बजरंग बिश्नोई, कौशल किशोर, शैलेंद्र चौहान, हृदयेश मयंक, नरेंद्र पुंडरीक,

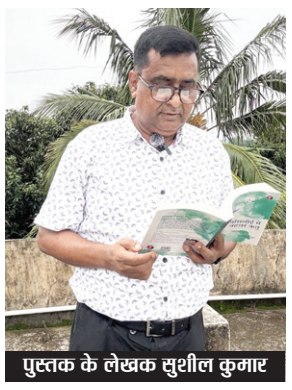
पुस्तक के लेखक सुशील कुमार

स्वप्निल श्रीवास्तव की रचनाओं की गहन और मर्मस्पर्शी काव्यात्मक उपस्थिति है। दूसरे खंड में सुशील कुमार ने पर्यावरण विषयक अपनी रचनाओं को शामिल किया है।

आलोचक की नजर में

यह रचना साहित्यिक जगह की कई परंपरागत मान्यताओं का विचलन करते हुए पाठकों के समक्ष एक नई अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करती है। रचना के लिए विषय का चुनाव ही सर्वोपरि रहा है। इसके अतिरिक्त भाषा, विधा के बंधन को तोड़ने का प्रयास किया गया है। कवि-लेखक इन रचनाओं को दो अलग-अलग किताबों में बांटकर अपनी कृतियों की सूची बढ़ाने के मोह में नहीं पड़ा है। यह पूरी रचना साहित्य और विशेष तौर पर हिंदी साहित्य को विषय अभाव के आरोप से मुक्त करती है। कवि-लेखक की यह रचना हिंदी साहित्य में पर्यावरण एवं साहित्य के पारिस्थितिकीय पाठ जैसे नवाचारी विषयों पर शोध कार्य करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी है।

कवि–लेखक के बारे में

हिंदी साहित्य जगत में सुशील कुमार की कविताएं अपनी अलग पहचान रखती हैं। झारखंड के जल, जंगल, जमीन की बात को साहित्य के राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सुशील कुमार झारखंड शिक्षा सेवा कैडर में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अब तक उनके पांच कविता संग्रह और दो आलोचना ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं।

Social Media Corner

सच के हक में...

थिरु सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुझे विश्वास है कि थिरु राधाकृष्णन जी एक असाधारण उपराष्ट्रपति बनेंगे और भारत के लोगों की एक सशक्त आवाज बने रहेंगे।

(रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 'एक्स' पर पोस्ट)

झारखंड की समृद्ध आदिवासी कला, सभ्यता, संस्कृति और दर्शन को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाले महान शिक्षाविद और कलाकार पद्मश्री डॉ रामदयाल मुंडा जी की जयंती पर शत-शत नमन।

(सीएम हेमंत सोरेन का 'एक्स' पर पोस्ट)

आदिवासी कला, संस्कृति और विचारधारा को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने वाले महान शिक्षाविद व कलाकार, पद्मश्री डॉ. रामदयाल मुंडा जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।

(कल्पना सोरेन का 'एक्स' पर पोस्ट)

बात चाहे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जैसे सीमावर्ती राज्यों की हो या अमेरीका और यूरोप के विकसित देशों की... घुसपैठ इन सभी जगहों के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

सेहतमंद भारत की मंजिल पर पहुंचने के पांच रास्ते

आजादी के बाद से भारत ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। साल 1947 में हमारी राष्ट्रीय जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, जो बढ़कर आज 70 वर्ष के आस-पास हो चुकी है। शिशु मृत्युदर समेत सभी आयु वर्गों में मृत्यु दर में कमी आई है। लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। फिर भी हम नई-पुरानी उपलब्धियों पर गर्वित होकर बैठ नहीं सकते। वैसे भी पुरानी चुनौतियां खत्म हो जाती हैं, तो नई सामने आती हैं और हमें उनके लिए तैयार रहना पड़ता है। वर्तमान में हमारे पास युवाओं की संख्या सर्वाधिक है, मगर आने वाले वर्षों में बुजुर्गों की तादाद काफी बढ़ने वाली है। जाहिर है, तब स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतें अलग किस्म की होंगी। इसके साथ ही देश में स्वास्थ्य संबंधी कई विषमताएं हैं। ये विषमताएं राज्यों के भीतर हैं, राज्यों के बीच में भी हैं और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में भी हैं। इनमें से कुछ चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में उपाय किए गए हैं, पर भविष्य की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पांच क्षेत्रों में ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है- सबसे पहले, देश में बढ़ते गैर-संचारी रोगों को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को नए सिरे से संगठित करने और इन केंद्रों को बुजुर्गों की सुविधा के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। साल 1950 के दशक से इस सदी के शुरूआती दौर तक, भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली संक्रामक रोगों और मां-बच्चे की स्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप चल रही थी। अब, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी गैर-संचारी बीमारियां आम हो गई हैं। इसलिए भारत में गैर-संचारी, संक्रामक और मातृ-शिशु संबंधी बीमारियों की तिगुनी जरूरत को पूरा करने के लिए इन केंद्रों को तैयार किया जाना चाहिए। 2017 में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी फॉर इंडिया में पाया गया कि देश में 60 प्रतिशत से अधिक मौतें गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण होती हैं। इसलिए, ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यक्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए इलाज को सस्ता बनाना होगा। दूसरा क्षेत्र, एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके अत्याधुनिक संक्रामक रोग निगरानी और उपचार एवं डाटा विश्लेषण प्रणाली तैयार करना है। स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए बढ़े बजट से इसे पूरा किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया और मौसमी सर्दी-जुकाम के नियमित प्रकोपों के अनुभव से महसूस किया गया है कि एक तत्पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सख्त जरूरत है। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों या जिला अस्पतालों को प्रहरी केंद्र के रूप में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तीसरा क्षेत्र शिशु विकास और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि अभी के बच्चे ही आगे युवा कार्यबल बनेंगे। चौथी बात, देखभाल के सभी स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करना चाहिए। भारत में अवसाद, चिंता, मादक द्रव्यों के सेवन और आत्महत्या जैसे मामलों की सर्वाधिक उपेक्षा की जाती है। अवसाद हर पांच में से एक गर्भवती महिला को प्रभावित करता है और हर साल लगभग 50 लाख महिलाएं इसकी शिकार बनती हैं। बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य भी अहम मुद्दा है। आखिर में, हमें एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दृष्टिकोण बनाने की जरूरत है। कुत्तों के काटने, मौसमी, मच्छर जनित और गर्मी से होने वाली बीमारियों में वृद्धि याद दिलाती है कि हमें समग्र रूप से सोचने की जरूरत है। भारत में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अस्वच्छता और शहरी भीड़ लोगों में श्वास संबंधी, पेट संबंधी और अन्य रोगों के प्रमुख वाहक हैं। शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, पुराने डीजल वाहनों को हटाना, औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को लागू करना और हरित बफर जोन बनाना जरूरी है। स्वस्थ भारत-2047 कोई आकांक्षा नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यक है। उपरोक्त पांच रणनीतिक और परस्पर जुड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके अगले दो दशकों में समन्वित, सुवित्तपोषित और समुदाय-आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करके, भारत अपने नागरिकों के स्वास्थ्य में बदलाव ला सकता है।

जरूरी सुधार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में सुधार से जुड़े केंद्र सरकार के प्रस्ताव साहसिक एवं वक्त की मांग के हिसाब से हैं। जैसा कि सरकार का दावा है, इन सुधारों से मध्यम वर्ग और व्यापारिक समुदाय को फायदा होगा। 12 फीसद वाले स्लैब में शामिल 99 फीसद वस्तुओं को 5 फीसद वाले तथा 28 फीसद वाले स्लैब में शामिल 90 फीसद वस्तुओं को 18 फीसदी वाले कर दर में स्थानांतरित करने से अधिकांश उपभोक्ताओं पर कर का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। स्लैब की संख्या को तर्कसंगत बनाने और एक जैसे उत्पादों को एक ही स्लैब में स्थानांतरित करने से अस्पष्टता और मुकदमेबाजी, जोकि वर्तमान जीएसटी व्यवस्था में व्यवसाय करने वाले लोगों की प्रमुख समस्याएं हैं, में भी कमी आएगी। इसके अलावा भले ही अधिकांश ध्यान करों की दर को नए सिरे से व्यवस्थित करने के प्रस्तावों पर केंद्रित किया गया है, लेकिन पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने और रिफंड से संबंधित प्रक्रियागत सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जीएसटी को सरल बनाने का मतलब सिर्फ दरों की बहुलता को कम करना ही नहीं, बल्कि करदाताओं के लिए इस प्रणाली को आसान और कम वक्तखाऊ बनाना भी है। इसलिए पंजीकरण को आसान बनाना, रिटर्न को सरल बनाना और रिफंड में तेजी लाना ऐसे स्वागत योग्य सुधार हैं, जिन पर केंद्र सरकार काम कर रही है। नए आयकर विधेयक और इस साल के बजट में आयकर स्लैब में नए सिरे से किए गए बदलाव के साथ-साथ जीएसटी के ये सुधार 2025 को कर सुधार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साल के रूप में रेखांकित करेंगे। यूं तो सरकार ने इन कटौतियों से राजस्व पर पड़ने वाले असर का आधिकारिक अनुमान नहीं लगाया है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि इससे राजस्व पर खासा असर पड़ने की आशंका है। दो साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने औसत जीएसटी दर 11.6 फीसदी होने का अनुमान लगाया था, जिसके अब काफी हद तक गिरने की उम्मीद है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

The quandary of quarry and hunter in Bihar

To a national leader with no determinate voter base, caste fealty, or proven experience in governance, the states are low-hanging fruits ready to be plucked, eaten, and savoured with an aftertaste of power. More so if a state falls in the Hindi heartland that still claims to offer the country its highest number of prime ministers.Rahul Gandhi fits the template. But in all fairness, he realised that just being a legatee from a premier political clan is not enough to reach for even a low-hanging fruit. Success is hard to get to in present-day politics, marked by a fluid social order in the wake of movements to empower the Other Backward Classes and Dalits, communal conflicts and, importantly, the emergence of a system that seems to increasingly make space for individuals with no pedigree to rise to the highest office through hard work and a smidgen of luck.Luck has not been on Rahul's side so far. Going against the Congress's grain and its traditional aversion to cohabit with smaller parties, he has had to compromise and forge alliances with entities and leaders who might have counted for nothing in the party's glorious decades. Rahul's campaigns in the recent past have been exceptionally aggressive towards the ruling BJP and its constituents, even if they have not yielded tangible outcomes.Now, Rahul is spearheading the attack on the Election Commission (EC) for allegedly fudging voters' lists and gerrymandering results to favour the party in power at the Centre and most states, at every tier of the power hierarchy including local bodies. The campaign was spurred by the EC's inexplicable move to conduct a Special Intensive Revision (SIR) of the Bihar electoral rolls just months before the state votes in October/November. The Congress is in alliance with the Rashtriya Janata Dal, the Left parties and the Vikassheel Insaan Party. The BJP's ally Nitish Kumar, who heads the Janata Dal (United), has been in power for 20 years—a record in politically volatile Bihar—by striking opportunistic deals. The RJD and its partners believe they can dislodge Nitish on the back of a widely-perceived anti-incumbency sentiment against his government.

But is a sustained campaign imbued with a crusading zeal against the EC's alleged omissions and commissions enough to see the back of Nitish? Certainly, Rahul is convinced it can. In and out of parliament's just-concluded session, Rahul mobilised the support of almost the entire non-BJP spectrum of parties who fear that if an SIR is carried out in their states, the spectre of defeat would loom large. West Bengal and Tamil Nadu, which have non-BJP governments, are examples.

Bihar is where the battle began to save the soul of democracy encapsulated in the one-person-one-vote precept enshrined in the Constitution. The BJP and its allies have regrouped under the NDA's banner, while the RJD and its partners have formed the Mahagatbandhan (MGB)—so the battle lines are firmly etched.A state election is eventually fought on local issues and helmed by a local leader or a coalition of leaders, even if a national cataclysm overwhelms the political landscape. Rahul, who apparently hopes to validate his national aspirations by using states as a vehicle, is reprising his Bharat Jodo Nyay Yatra with a 20-day Voter Adhikar (Voter Rights) peregrination in the state that started with a rally at Sasaram.The difference emerging in the impending election and the last assembly poll in 2020 is Tejashwi Yadav, Lalu Prasad's political heir and the chief protagonist five years ago. Rahul was almost absent in that campaign. Under Tejashwi's stewardship, the RJD emerged as the single largest party followed closely by the BJP, while Nitish's JD(U) stood a poor third. Like other present-day inheritors, Tejashwi did not have it easy to begin with.

Constitution's Ninth Schedule: An innovation born in Madras

On Madras Day, it's instructive to remember a constitutional innovation proposed by V K Thiruvenkatachari, advocate-general of Madras state in the 1950s, which eventually became the Ninth Schedule. It still provokes some of the fiercest debates between the judiciary and the legislature

The city once called Madras evokes memories of its stately monuments, soulful music and the lingering glow of Marina sunsets. Yet on this Madras Day, it is worth recalling a story less often told—how a Madras lawyer's idea travelled to Delhi, rewired the Constitution, and still shapes some of the fiercest debates between the legislature and the judiciary.

In the early years after independence, few issues burned hotter than the demand to dismantle the zamindari system. Born of colonial land settlements, it left a small class of intermediaries holding vast tracts, while millions of cultivators tilled without ownership. The Congress had long promised its abolition, and state governments moved quickly to enact sweeping reform laws. These aimed not just to redistribute land but to reorder rural power structures, clearing the ground for a more egalitarian society.

The backlash was immediate. Zamindars and intermediaries challenged the reforms, and the courts—bound to interpret and apply constitutional provisions as they stood—arguably proved sympathetic. The Patna High Court, for instance, struck down the Bihar Land Reforms Act, 1950, holding it inconsistent with the right to property under what were then Articles 19(1)(f) and 31 of the Constitution (Kameshwar Singh, 1951).This was no ordinary constitutional tussle. Land reform was a political promise with immense social stakes. Without it, economic inequality and feudal control would persist. But the rulings revealed a deep cleavage in the constitutional order—between the promise of individual rights on one side and the democratic mandate to dismantle centuries-old hierarchies on the other.It was at this impasse that V K Thirvenkatachari, the then advocate general of Madras state, wrote a letter to the Union law secretary proposing a constitutional innovation. His simple yet radical idea suggested the creation of a separate schedule to the Constitution where certain laws could be placed, shielding them from challenge under the Fundamental Rights chapter.

The plan took a two-pronged form. Article 31A would specifically protect land laws on agrarian reform and abolition of intermediaries from being struck down for violating rights such as those to property or equality. Article 31B went further—any law placed in a new Ninth Schedule would be completely beyond the courts' reach. Parliament adopted this idea wholesale into the Constitution (First Amendment) Act, 1951, thus inaugurating Articles 31A, 31B and the Ninth Schedule.

As the American constitutional historian Granville Austin observed in Working a Democratic Constitution, this was an extraordinary assertion of parliament's will to push social policy past the courts' barricades—and a vivid example of the founding generation's struggle to balance social revolution with constitutional restraint. Indian historian Tripurdaman Singh, in Sixteen Stormy Days: The Story of the First Amendment to the Constitution of India , calls the Ninth Schedule one of the most divisive elements of Nehru's first constitutional amendment, a live test of how far a democracy could insulate bold policy from judicial review without corroding the very liberties it sought to uphold.For decades, the arrangement held. In Sankari Prasad Singh Deo (1951), the Supreme Court upheld the Ninth Schedule's immunity, effectively creating a political-judicial truce. Reformist laws could be protected from litigation, giving the legislature room to pursue a redistributive and regulatory agenda, while the court's larger interpretive authority over the Constitution remained formally undisturbed. Through the 1950s and 60s, the Ninth Schedule became an impregnable vault for laws on land reforms, industrial regulation and social welfare.But the balance shifted in the 1970s. In Kesavananda Bharati (1973), where a 13-judge bench articulated the now-foundational 'basic structure' doctrine, holding that parliament's amending power under Article 368 could not be used to alter the Constitution's essential framework. This principle eventually came home to the Ninth Schedule, most squarely in I R Coelho (2007), where the court ruled that post-1973 entries could be struck down if they violated the Constitution's basic structure.Thiruvenkatachari's 'impregnable armour' now bore apertures: the shield still stood, but judicial review had found a way to penetrate its walls.Today, the same questions that may have haunted the 1950s have returned. Legislatures still reach for the armour of insulation when passing contentious laws. The Maharashtra (Socially and Educationally Backward Classes) Act attempted to exceed the 50 percent reservation ceiling, only to be struck down in 2021. Expansive welfare schemes are ring-fenced to escape fiscal scrutiny. Most recently, the 103rd Constitutional Amendment creating the economically weaker sections quota was defended in Janhit Abhiyan(2022) partly on the claim that affirmative action must be shielded from judicial review.The old dilemma refuses to die: does placing a law beyond review fortify the march of social justice, or does it erode the promise of equality, federalism and fundamental rights on which the Constitution stands?As Justice Rohinton Nariman notes in The Basic Structure Doctrine: Protector of Constitutional Integrity, the survival of our constitutional order depends not on the absence of conflict between the legislature and the judiciary, but on the fidelity of each to the boundaries that the Constitution has drawn.On this Madras Day, that is more than a legal truism—it is a tribute to a city whose legal imagination once bent the arch of India's constitutional history, and a reminder that the spark lit by Thiruvenkatachari continues to illuminate India's journey.

School mergers raise concerns about access

Rather than merging schools, it is pertinent to ask why parents are withdrawing their children from schools. The answers are well known: inadequate facilities, teacher absenteeism, and a lack of accountability

The Uttar Pradesh government's decision to merge over 10,000 government primary and upper primary schools with fewer than 50 students has triggered a serious debate. The move is explained as being in line with the National Education Policy 2020, which encourages school clusters and resource sharing for improving learning environments. Several states are taking similar steps, suggesting that this is becoming a broader trend in the management of primary education. However, concerns are being raised and legal redress is being sought. The Right to Education Act, 2009 guarantees free and compulsory education in neighbourhood schools for children aged between six and 14. The Act does not set any minimum enrolment requirement for schools to exist. Closing or merging schools in ways that make them less accessible poses a risk of diluting the neighbourhood principle that underpins the law. Neither the NEP nor a government order can supersede children's fundamental right enshrined under Article 21A of the Constitution.

Besides the legal concerns, the education ministry has pointed out declining enrolments in many government schools, a trend confirmed by UDISE+ data. Rather than merging schools, it is pertinent to ask why parents are withdrawing their children from schools. The answers are well known: inadequate facilities, teacher absenteeism, and a lack of accountability. These are failures of governance rather than a lack of demand for education. If resources were directed towards improving infrastructure, training teachers, and ensuring consistent quality, enrolments could rise again. For many families in towns and villages, especially for the marginalised, a nearby school is what makes education possible. When that school is shut, the burden of distance falls on the child, girls in particular. When schools move farther away, dropout rates for girls rise sharply. In UP, with a 57.18 percent female literacy rate, the loss of neighbourhood schools can only deepen the existing inequalities.

Such mergers may appear efficient in the short term, but the long-term costs could be considerable. A practical approach would be to strengthen the schools that already exist—by improving classrooms, ensuring teachers' presence, and making schools centres of community trust. The constitutional promise under Article 21A is not simply about costeffective administration. It is about opening doors of opportunity for every child, regardless of background. Ensuring that neighbourhood schools remain accessible and vibrant is central to that promise.

Why India Should Get Its Tibet Strategy Straight

China's massive rail and dam projects in Tibet threaten India's security and Tibetan autonomy. New Delhi must balance firm border defense with diplomatic support for Tibet

China is set to build the most ambitious rail link connecting Xinjiang province with Tibet, part of which will "run near" the Line of Actual Control (LAC) with India. This is not the only mega construction in the region. Just last month, China started construction of the world's biggest dam over the Brahmaputra River in ecologically fragile Tibet, close to Arunachal Pradesh. These developments mark a significant escalation in China's infrastructure expansion in the Himalayan region.

The Xinjiang-Tibet Railway Company (XTRC), registered with an initial capital of 95 billion yuan and wholly owned by the China State Railway Group, has been tasked with constructing this strategic line. According to media reports, the project is part of a broader plan to create a 5,000-kilometre plateau rail framework anchored on Lhasa by 2035.While the registered capital represents only a small initial investment, the overall costs are expected to be far higher, comparable to the 320 billion yuan spent on the 1,800-kilometre Sichuan-Tibet Railway. The route, averaging over 4,500 metres in elevation, will traverse key Himalayan regions such as the Kunlun, Karakoram, Kailash and other mountain ranges.Certain sections of this railway line will allegedly run very close to the LAC. There is, thus, clear defensive and strategic value in this project for India. Furthermore, this mirrors China's earlier construction of the Xinjiang-Tibet Highway through Aksai Chin, which was a key trigger of the 1962 Sino-Indian conflict. Thus, the construction of the Xinjiang-Tibet Railway link reinforces the strategic stakes for India, given its historical and cultural ties with the region and claims over the territory.

Expanding on the proposed railway link, it is one of four planned rail lines linking Tibet to the rest of China. The new line will come up alongside the already operational Qinghai-Tibet route and two others under construction from Sichuan and Yunnan. Furthermore, these projects are coming at an extremely delicate moment for India-China relations, as Beijing and New Delhi have just recently begun thawing relations after years of standoff along the border. Thus, by inaugurating this project just ahead of high-profile diplomatic engagements with India and the US, China is showcasing its determination to consolidate its grip over the Tibetan plateau through connectivity, integration and military preparedness.Simultaneous to the rail link, China has also begun construction of the world's largest hydropower dam over the Yarlung Tsangpo River in Nyingchi, Tibet, close to Arunachal Pradesh. According to China, it will generate an annual output of roughly 300 billion kilowatt-hours (approximately three times that of the Three Gorges Dam) and form part of China's long-standing 'West-to-East Electricity Transfer Project', which aims to move power from resource-rich western regions to the industrialised east.

The dam's location has raised grave concerns about water security and weaponisation of water for downstream states like India and Bangladesh. Additionally, its location near the Great Bend, just before the river enters India as the Brahmaputra, has strategic consequences of ecological disruption and the potential weaponisation of transboundary flows during wartime.Also, since it is positioned in a seismically active Himalayan zone, the risks of structural failure and catastrophic flooding cannot be discounted. Indian officials have voiced these concerns formally to Beijing, with Arunachal Pradesh leaders calling it a "water bomb". Bangladesh has also sought greater transparency on the project's implications.These mega projects in Tibet are not isolated engineering projects but components of a deeper strategic vision. Tibet remains central to China's resource extraction, energy generation and territorial consolidation goals. The region holds immense untapped hydropower potential. Research indicates over 110 gigawatts are yet to be harnessed. In this context, Beijing has steadily expanded its infrastructural footprint on Tibetan rivers over the past decade. Furthermore, this infrastructure push aligns with the political project of integrating minority regions more fully into the Chinese community."Integration" (jiaorong; ??) in this context is, thus, a euphemism for cultural assimilation, economic incorporation and demographic transformation. Tibetans have resisted these coercive policies and measures for decades, but China has doubled down on the region and its ethnic people by constantly advancing infrastructure, resettlement and even ideological education.Beijing's control over Tibet extends far beyond the territory's geographical landscape and tangible assets, reaching to the very heart of its cultural and religious identity. The Chinese state has imposed sweeping restrictions on religious practice, language use and political expression, with no Tibetan ever having held the top political position of Party Secretary in the so-called Tibet Autonomous Region (TAR) since its establishment in 1965.The disappearance of the Panchen Lama recognised by the Dalai Lama in 1995, the banning of the Dalai Lama's image and the forced use of Mandarin in schools only further exacerbate the erosion of Tibetan autonomy. International bodies such as the United Nations have, for decades, issued resolutions and statements urging China to respect Tibetan rights, but these appeals have been repeatedly ignored. Access for independent observers remains heavily restricted. China consistently rejects allegations of abuses as politically motivated interference, leaving no avenue for dialogue.However, forced assimilation in Tibet is not only ideological but also physical. In recent times, Beijing has implemented large-scale relocation programmes in the region, moving Tibetans from remote highland areas to urban settlements. This is often done under the pretext of "improving livelihoods".

Trump turns $11.1B in US government funds into a 10% stake in downtrodden Intel

The US government's stake in Intel coincides with Trump's push to bring production to the US, which has been a focal point of the trade war that he has been waging throughout the world.

WASHINGTON.(Agency)

President Donald Trump on Friday announced the US government has secured a 10% stake in struggling Silicon Valley pioneer Intel in a deal that was completed just a couple weeks after he was depicting the company's CEO as a conflicted leader unfit for the job."The United States of America now fully owns and controls 10% of INTEL, a Great American Company that has an even more incredible future," Trump wrote in a post.

The US government is getting the stake through the conversion of $11.1 billion in previously issued funds and pledges. All told, the government is getting 433.3 million shares of non-voting stock priced at $20.47 apiece — a discount from Friday's closing price at $24.80. That spread means the US government already has a gain of $1.9 billion, on paper.

The remarkable turn of events makes the US government one of Intel's largest shareholders at a time that the Santa Clara, California, company is in the process of jettisoning more than 20,000 workers as part of its latest attempt to bounce back from years of missteps taken under a variety of CEOs.Intel's current CEO, Lip-Bu Tan, has only been on the job for slightly more than five months, and earlier this month, it looked like he might be on shaky ground already after some lawmakers raised national security concerns about his past investments in Chinese companies while he was a venture capitalist. Trump latched on to those concerns in an August 7 post demanding that Tan resign.But Trump backed off after the Malaysian-born Tan professed his allegiance to the US in a public letter to Intel employees and went to the White House to meet with the president, leading to a deal that now has the US government betting that the company is on the comeback trail after losing more than $22 billion since the end of 2023. Trump hailed Tan as "highly respected" CEO in his Friday post.

In a statement, Tan applauded Trump for "driving historic investments in a vital industry" and resolved to reward his faith in Intel. "We are grateful for the confidence the President and the Administration have placed in Intel, and we look forward to working to advance US technology and manufacturing leadership," Tan said.Intel's current stock price is just slightly above where it was when Tan was hired in March and more than 60% below its peak of about $75 reached 25 years ago when its chips were still dominating the personal computer boom before being undercut by a shift to smartphones a few years later. The company's market value currently stands at about $108 billion - a fraction of the current chip kingpin, Nvidia, which is valued at $4.3 trillion.

Gaming cos exit real money gaming following new legislation

MUMBAI.(Agency)

Hit by increased scrutiny and regulation, India's online gaming industry is undergoing decisive change. Following the passage of the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025, several startups have discontinued their real money gaming (RMG) operations.Fantasy sports giant Dream11 announced the suspension of its cash contests. In a message to users, Dream11 said: "As per 'The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025', cash games and contests will be discontinued on Dream11."Last valued at $8 billion in 2021, Dream11 has more than 280 million users. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) onboarded Dream11 as Team India's official shirt sponsor under a ?358 crore deal running from July 2023 to March 2026.Nazara Technologies' Moonshine Technologies, which operates real money gaming platform PokerBaazi, also moved to comply with the new law. "...We wish to inform that, as a matter of abundant caution and in due respect of the government's mandate, Moonshine Technologies Pvt Ltd (Moonshine/Pokerbaazi), an associate company in which Nazara holds a 46.07% stake, has ceased offering real money online gaming operations. The company will evaluate the future course of action following the enactment of the Bill," Nazara said in an exchange filing.Nazara shares fell another 5% on Friday. The company has invested ?805 crore in Moonshine and committed an additional ?255 crore via compulsorily convertible preference shares.

Unicorn startup Games24x7 has also discontinued its real money gaming app RummyCircle. Its fantasy app My11Circle has likewise shut down real money gaming options."All players will be able to seamlessly withdraw any balance from their wallets and we will make sure the process is smooth and hassle-free. From this point on, no new cash deposits will be accepted, and games involving real money will not be available on our platform," Games24x7 said in a post on X on Friday.

EPF, PPF Interest Won't Be Taxed—But Hiding It Could Cost You Big

New Delhi.(Agency)

Even though the interest earned on EPF (Employees' Provident Fund) and PPF (Public Provident Fund) accounts is tax-exempt, tax professionals recommend reporting it in your annual Income Tax Return (ITR). Doing so promotes transparency and helps avoid future complications.

EPF Interest: Condition-Based Exemption

Interest from EPF is exempt only when an employee stays in continuous service for five years or more. If the balance is withdrawn before completing this period, the tax benefits are reversed. This means:The employee's contribution (if tax benefits under Section 80C were claimed), and

For instance, if you withdraw Rs 1.5 lakh from your EPF before five years, including Rs 20,000 of interest, the entire sum could be treated as taxable income. Each component of the withdrawal is taxed separately, depending on the nature of the contribution.PPF Interest: Always Exempt

Interest earned on PPF is completely tax-free under Section 10(11) of the Income Tax Act. Contributions, accrued interest, and withdrawals all remain exempt, regardless of how long the account is held. Still, experts advise declaring accrued interest each year in Schedule EI (Exempt Income) of the ITR for accuracy.

Why Declare Even Exempt Income?

While there's no penalty for not reporting such exempt interest, voluntarily disclosing it helpsBuild a clear financial trail,Prevent possible questions from tax authorities later, andStrengthen your financial records, especially when using large funds for big-ticket investments or purchases.Not reporting exempt interest may not cause immediate issues, but declaring it consistently is a best practice. It improves transparency, minimizes the risk of disputes, and ensures your financial records remain reliable.:

CCPA Fines VLCC Limited Rs 3 Lakh Lor Misleading Fat-Loss Ads On CoolSculpting

New Delhi.(Agency)

The Central Consumer Protection Authority (CCPA) has imposed a penalty of Rs 3 lakh on VLCC Limited for publishing misleading advertisements regarding fat-loss and slimming treatments through the use of the US-FDA approved CoolSculpting procedure/machine.Earlier, CCPA had also levied a penalty of Rs 3 lakh on Kaya Limited for publishing misleading advertisements on CoolSculpting treatments.The company's advertisements claimed "Kaya's Non-surgical Fat Reduction" and "Kaya brings you easy inch loss with CoolSculpting," and even depicted misleading before-and-after images suggesting major fat loss all over the body. These claims went beyond the actual US-FDA approval and misrepresented the procedure as a weight-loss treatment. Kaya Limited has since complied with the CCPA's order and deposited the penalty amount," Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution said in a release.The matter of VLCC Limited came to the notice of CCPA through a complaint and monitoring of advertisements in the slimming and beauty sector.

"On examination, it was found that VLCC was making exaggerated claims of drastic weight loss and inch reduction within a single session, which went far beyond the actual approval granted to the CoolSculpting machine, thereby misleading consumers," Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution release said.The investigation revealed that the advertisements of VLCC projected CoolSculpting and related procedures as a permanent weight-loss and size-reduction solution.

SEBI plans incentives for first-time women mutual fund investors: SEBI Chairman

New Delhi .(Agency)

SEBI is planning to come up with additional incentives in order to help and encourage the first-time female investors to participate in the mutual funds, said SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey on Friday."Financial inclusion will remain incomplete unless women are equally represented," said Pandey while speaking at an event organised by the Association of Mutual Funds in India (AMFI).We are thus also envisaging to introduce an additional distribution incentive for investments from first-time women investors," he added further.

Incentives for First-Time Women investors in B30 Cities

He said that SEBI is taking a slew of measures to facilitate and encourage the industry, and one such proposal is to incentivise the distributors for investment from first-time individual investors in B30 cities, which comprise tier 2 and tier 3 cities.The move is set to bring new investors into the mainstream equity market while simultaneously extending the reach of mutual fund into underrepresented and underserved regions, which will therefore contribute to financial inclusion.Additionally, to address legacy issues of the mutual fund industry, such as overlap in the portfolio schemes, SEBI is reviewing the categorisation of mutual fund schemes.He further said that based on the feedback from various industry stakeholders and from the consultation process, further steps will be taken.

"These measures are expected to facilitate the industry to become more transparent and investor-friendly," the Sebi chairman said.Lately, SEBI has reviewed reports and filings submitted by mutual funds in order to promote ease of doing business measures and to streamline the compliance process.

Based on the review, the regulator has decided to discontinue the requirement of filing over 52 reports, notices, and addendums with it by the asset management companies (AMCs).

SEBI's Future Roadmap

The future roadmap of SEBI includes the regulator working towards a comprehensive simplification of mutual fund regulations. The end goal is to ease the compliance burden for the industry players while continuing to safeguard the investor interest, said Pandey.

Nifty rejig: Indigo, Max Health in; Indusind, Hero out

MUMBAI .(Agency)

The National Stock Exchange (NSE) has decided to add the airline major Interglobe Aviation that operates the largest airline Indigo and the hospital-chain Max Healthcare into the benchmark Nifty 50, replacing the troubled lender Indusind Bank and the two-wheeler major Hero Motocorp effective September 30.

The largest bourse said late Friday that both the inclusion as well as the exclusion are part of the semi-annual rejig of the index, based on free float market value of the 50-stock index components. The NSE index subcommittee met to take the calls. The NSE's biannual index reshuffle is based on stocks' average free-float market capitalization over six-month periods ending January 31 and July 31, with the changes implemented in March and September, respectively. The BSE does this recast in every July and December based on the same methodology and principles.

Changes to the Nifty 50 usually lead to reshuffling of exchange traded funds linked to the benchmark index, which could result in several million dollars worth of inflows and outflows for the stocks that are rejigged.

Entry into the index could bring in $400 million for Max Healthcare, while Interglobe may see an inflow of $600 million, according to an estimate by Nuvama in July.For the year through July-end, shares of Max and Interglobe rose 9.34% and 28.61%, respectively, while those of Indusind fell 17.59%. Hero's stock was up 1.82%.According to an analysis of Nuvama Alternative, with the index rejig, exchange-traded funds and mutual funds that track the Nifty will have to now rebalance their portfolios to align with the new index composition, which leads to changes in passive fund flows.The impact of the exclusion on Indusind, which since the March accounting scam in March, will be hard going forward. The bank took a $230 million hit in the year ended March 31 due to misaccounting in internal derivative trades, prompting the resignations of CEO Sumant Kathpalia and his deputy Arun Khurana late April. While the two-wheeler major may see $600 million in outflows, the troubled lender is likely to see an outflow of $230 million according to brokerages. During the last rejig in March, Zomato and Jio Financial entered the index, replacing state-run petroleum major BPCL and the food major Britannia Industries. When the Sensex was recast last May, with effective changes from July 23, the Tata group's retail arm Trent and the public sector Bharat Electronics replaced Nestle India, and Indusind Bank.

Gold shines brighter: Is now the right time to buy amid Fed rate cut buzz

CHENNAI.(Agency)

Gold prices continued their upward trend on Friday, August 23, supported by growing expectations of a US Federal Reserve rate cut after Jerome Powell's dovish comments at the Jackson Hole symposium. His signal that the Fed may ease policy soon to counter slowing growth and tariff-related inflation risks pushed US bond yields lower and weakened the dollar, which in turn boosted demand for gold.

Safe-haven buying also added momentum as investors remained cautious about global trade frictions and currency volatility. Technically, gold held firmly above short-term support levels and moved closer to its recent highs, indicating strong buying interest in the market.The current rally has raised the question of whether this is the right time to buy gold. In the positive case, if the Fed begins cutting rates, real yields are likely to fall further, which has historically supported gold prices. A weaker dollar would also enhance gold's appeal for global investors. On the other hand, there are risks in the short term. Any profit-taking after the recent rally or a sudden shift in Fed communication could lead to volatility. Stronger-than-expected US economic data could also reduce the chances of aggressive rate cuts, which may cause a temporary pullback in gold.

For long-term investors, the macroeconomic backdrop remains supportive, and gold can be accumulated gradually, particularly on price dips. For short-term traders, it may be prudent to watch resistance levels closely and manage risk carefully.Overall, the uptrend in gold appears intact and expectations of Fed rate cuts strengthen the outlook for further gains. While chasing the rally may carry near-term risks, buying on declines could be a more balanced strategy.

MSMEs pin hopes on GST revamp for easier compliance, input tax credit

Business owners say that despite nearly eight years of GST, bureaucratic hurdles — particularly at the state level — continue to weigh them down

MUMBAI.(Agency)

As the government prepares to roll out GST reforms by Diwali, micro, small and medium enterprises (MSMEs) are hoping for simpler registration, compliance, and refund processes. Business owners say that despite nearly eight years of GST, bureaucratic hurdles — particularly at the state level — continue to weigh them down.According to Vinod Kumar Wuthoo, President of the SME Forum, the churn within the GST system highlights compliance fatigue. "Nearly 1.75 lakh GST registration revocations and around 1.5 lakh cancellations occur every single month, reflecting the procedural fatigue and compliance difficulties faced by businesses," he said.

A West Bengal-based MSME owner, requesting anonymity, alleged that due to the lack of process automation, they are often harassed by state officials for bribes. Several entrepreneurs echoed similar concerns, pointing out that irrelevant show-cause notices (SCNs) are frequently issued, only to be dropped later.Muzaffarnagar-based entrepreneur Neeraj Kedia, managing director of zinc sulphate manufacturer Chakradhar Chemicals, recalled once receiving a demand notice of ?95 lakh with an additional ?1.15 crore in interest for July 2017 to March 2018. "In most cases, the notices are dropped. There should be mandatory reporting of how many show-cause notices actually stand the legal test," Kedia said. He added that, often, even after satisfactory explanations, state officials proceed with tax impositions.

ITC conundrum

Input tax credit (ITC) allows businesses to claim reimbursement for taxes paid on purchases. However, under the current system, businesses cannot claim ITC on items taxed at 5% because of the inverted duty structure. With the government considering moving a significant share of goods from the 12% slab to 5%, industry representatives have urged that ITC be extended. "The input credit system must remain intact; otherwise, for regular FMCG products (likely to fall under the 5% slab), the retail market will shift entirely to big players like Amazon and Reliance who buy directly from manufacturers. Local stores — which usually buy from distributors — will be severely hit," said Rakesh Chhabra of the RAI Industries Association, Sonipat, Haryana.

Compliance burden

Currently, dealers must file GSTR-1 by the 11th of every month, while GSTR-3B — a non-revisable return — is due by the 20th. Late filing attracts penalties. Many MSMEs want this gap extended to ease compliance pressures. "We would like GST to be simpler, like income tax. Laws are very subjective and, overall, GST remains a complex taxation system," said Harsh Mittal, MD & CEO of MITASO Comtel.

CBI raids Anil Ambani's Mumbai home in Rs 17,000-crore SBI-loan fraud case

▸The CBI on Saturday raided Anil Ambani's Mumbai residence in connection with a Rs 3073 crore bank fraud case, days after ED also expanded its probe and summoned his top executives.

Agency New Delhi.

The Central Bureau of Investigation (CBI) on Saturday morning conducted searches at industrialist Anil Ambani's residence in Mumbai in connection with a bank fraud case worth Rs 3,073 crore.Officials reached Ambani's residence at Seawind, Cuffe Parade, around 7 am. According to sources, "seven to eight officials" arrived at the premises and have been carrying out the search since then. Ambani and his family are present at the residence while the searches are underway.

The CBI filed a fresh FIR against Anil Ambani, his business entities and others based on a complaint by State Bank of India (SBI) alleging fraud. The FIR has been lodged in Delhi.

In its complaint, SBI alleged a total fraud of Rs 3,073 crore by Anil Ambani's Reliance Communications Limited (RCOM). The bank had earlier classified the account and promoters, including Anil D Ambani, as "fraud" on November 10, 2020, and filed a complaint with CBI on January 5, 2021. However, the complaint was returned due to a "status quo" order issued by the Delhi High Court on January 6, 2021.

The State Bank of India has now officially classified Reliance Communications Limited (RCOM) and its promoter director, Anil D Ambani, as "fraud," Minister of State in the Ministry of Finance Pankaj Chaudhary informed the Lok Sabha on Friday.

In a written reply, Chaudhary said that SBI made the classification on June 13, 2025, under the Reserve Bank of India's Master

Directions on Fraud Risk Management and the bank's internal policy. As part of disclosure norms, RCOM's Resolution Professional informed the Bombay Stock Exchange about the classification on July 1, 2025.According to the minister, SBI's total exposure to RCOM includes a fund-based principal outstanding of Rs 2,227.64 crore with accrued interest and expenses since August 26, 2016, along with non-fund-based bank guarantees worth Rs 786.52 crore.RCOM is currently undergoing the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Committee of Creditors approved a resolution plan, which was filed with the National Company Law Tribunal (NCLT), Mumbai, on March 6, 2020, but is still awaiting final approval. SBI has also initiated a Personal Insolvency Resolution Process against Anil Ambani under the IBC, which is being heard by NCLT Mumbai.

This is not the first time the Ambani-led telecom firm has faced such action. SBI had earlier classified RCOM and Anil Ambani as "fraud" in November 2020 and filed a complaint with CBI in January 2021.

Following a Supreme Court ruling on March 27, 2023, which mandated lenders to give borrowers an opportunity to present their case before being labelled as fraud, SBI reversed the classification on September 2, 2023.

The bank later re-ran the process in compliance with an RBI circular dated July 15, 2024, and reclassified the account as fraud.On June 24, 2025, SBI reported the classification to the Reserve Bank of India and said it is in the process of lodging a formal complaint with the CBI. Following this, the CBI filed an FIR in the case.

Cheque bounce case: Delhi court fines man Rs 10K for 'mischievous' plea

Agency New Delhi.

A Delhi court has come down heavily on a litigant for what it described as a "mischievous" attempt to misuse judicial remedies, imposing a fine of Rs 10,000 and dismissing his petition. The court stressed that while access to justice is fundamental, it cannot be abused to create chaos, delay proceedings or obstruct the course of law.The matter arose from a revision petition filed by Soumya Ranjan Kanungo, who challenged a magistrate's August 2024 order refusing to stay a non-bailable warrant (NBW) issued against him in a cheque bounce case. Additional sessions judge Bhupinder Singh, in an order dated August 18, observed that the magistrate's decision was correct, as the warrant was issued only to secure Kanungo's appearance and did not affect his legal rights.

"Instead of submitting himself to the jurisdiction of the trial court, the revisionist has been trying to subvert the course of justice by filing the present revision petition," the judge said, noting that the order under challenge was "purely interlocutory" and not open to revision.

He added that even on merits, the plea had no substance. The court also underscored Kanungo's repeated absence from trial, pointing out that proceedings had been stalled for more than five years. "The trial court has rightly observed that the revisionist has taken undue advantage of the liberty granted to him," the order stated.It further recorded that "even in the present case, Kanungo took much liberty, and every time different counsel appeared on his behalf and sought adjournments for addressing the arguments."Expressing strong disapproval, Judge Singh said he was anguished and appalled by the litigant's "insidious and cavalier approach". The order also said, "In my view, liberal access to justice should not be construed by anyone as a means to lead to chaos and indiscipline, and frivolous petitions should be penalised with heavy costs."

'Victory of compassion': Activists

Agency New Delhi.

Cheers and tears of relief erupted at Jantar Mantar on Friday after the Supreme Court modified its earlier order mandating the relocation of stray dogs in Delhi-NCR. The three-judge bench clarified that only rabid or aggressive dogs could be shifted to shelters, while healthy strays must be sterilised, vaccinated and returned to their original areas as prescribed under the Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023. Civic bodies were also told to set up designated feeding zones in every ward, based on the concentration of community dogs.

As the ruling was pronounced, activists and caregivers present at the protest site embraced, shouted slogans and thanked God, calling the verdict a "victory of compassion". Several described it as historic, saying it secured the future of "street kids" who would now continue to live among their caregivers. For many, the relief was palpable after days of uncertainty sparked by the August 11 directive that ordered the relocation of all strays to shelters, a move widely criticised as unfeasible given the lack of infrastructure.

Animal rights groups welcomed the judgement.PETA India urged authorities to implement feeding areas and encouraged adoption over pet purchases, adding that "today is the day for Sheru at the tea stall, Rani at the mandir steps and Moti in the society grounds." The SC's ruling also drew a mixed response from resident groups. Sanjay Gupta, president of the Model Town Residents Society, said while the order permitting the feeding of dogs only in designated MCD areas would reduce conflicts and make public spaces safer, concerns remained.

"We are disappointed that dogs will not be moved to shelters. Strays suffer neglect, disease and accidents. "The government must create shelters and conduct an immediate census," he said.The association also urged strict monitoring and swift implementation, stressing that lapses by civic authorities had worsened the crisis.

MCD's 'mosquito terminator train' to tackle dengue

Agency New Delhi.

The Municipal Corporation of Delhi (MCD), in collaboration with Northern Railway, on Friday launched a major campaign to control mosquito-borne diseases in the capital. Mayor Raja Iqbal Singh flagged off the 'Mosquito Terminator Train' from New Delhi Railway Station. Through this train, anti-larval chemicals will be sprayed in a radius of 50–60 metres on both sides of the railway tracks.

For this purpose, a special truck equipped with a power sprayer has been mounted on a railway wagon, enabling easy spraying of anti-larval chemicals even in difficult-to-reach areas.

Singh said that the MCD is fully committed to the health and safety of citizens. Due to rains, water often accumulates around railway tracks, creating breeding grounds for mosquitoes.With the 'Mosquito Terminator Train', large-scale spraying will help us eliminate diseases like dengue, malaria, and chikungunya from their root. He added, This is not just a train, but a shield to safeguard the health of Delhiites, reaching areas that cannot be manually accessed.

MCD Commissioner Ashwini Kumar stated that this joint campaign of MCD and Railways is an important initiative in public interest. This collective effort will bring relief to lakhs of people. He further added that the Municipal Corporation is carrying out cleanliness and mosquito eradication drives in a mission mode. However, this campaign will only be successful if every citizen participates.

He appealed to the people of Delhi to ensure that water does not stagnate in and around their homes, to maintain cleanliness, and to actively support the Corporation's efforts. Community participation is key in the fight against mosquitoes and related diseases,he emphasized. The commissioner added that the drive, which will continue until September, is expected to significantly help in controlling mosquito-borne diseases.

India's Big Leap: Home-Built Engines For 'Made In India' 5th-Gen Stealth Jets

Speaking at the ET World Leaders' Summit, Mr Singh said that engine manufacturing work is about to begin in India jointly with the French company Safran.

Agency New Delhi.

India will indigenously build its fifth-generation fighter aircraft and aircraft engines, Defence Minister Rajnath Singh has announced, reflecting the country's resolve to become self-reliant in the Defence sector. Speaking at the ET World Leaders' Summit, Mr Singh said that engine manufacturing work is about to begin in India jointly with the French company Safran.

"Today, we have also taken steps forward in the direction of building Fifth Generation fighter aircraft. We have also moved towards manufacturing the aircraft's engine in India itself. We are about to start engine manufacturing work in India with the French company Safran," the minister said.

India has been working on the ambitious 'Advanced Medium Combat Aircraft'

(AMCA) project to build the country's first fifth-generation jet. Under the project, five prototypes of the AMCA are being planned, and the Aeronautical Development Agency (ADA) under the Defence Ministry has invited an Expression of Interest for developing these prototypes.

Speaking at the Summit, he also highlighted the recent breakthroughs in indigenous capability, pointing to the Tejas light combat aircraft as a "splendid example"."Our Tejas aircraft is going to be a great example of India's indigenous defence capabilities. It's not that we aren't facing challenges in this endeavour, but we have resolved that we will find solutions to every problem and will definitely establish the full capability to build fighter aircraft in India," the minister said.

The AMCA, along with the Tejas light combat aircraft, are planned to be the mainstay of the Indian Air Force.

The Defence Minister also shared an update related to Hindustan Aeronautics Limited (HAL) while talking about India's indigenous defence capabilities. Besides earlier orders for 83 aircraft worth Rs 48,000 crore, the HAL has received new orders worth Rs 66,000 crore for 97 Tejas fighter aircraft, he said.

IIT Delhi develops AI model for instant cement quality checks

Agency New Delhi.

Researchers at the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi have developed artificial intelligence (AI) models capable of predicting the quality of cement clinker—the key component in cement production—in a fraction of a second, potentially revolutionising the global construction industry.

Cement is the backbone of the built environment, with over 4.1 billion tonnes produced annually worldwide. India is the second-largest producer, and the sector is among the most carbon-intensive industries, accounting for nearly 8% of global CO2 emissions. Producing one tonne of cement alone releases 0.66 tonnes of CO2—equivalent to driving a petrol car from Paris to Istanbul. Traditionally, cement quality has been tested using high-energy X-rays on clinker, a process that takes several hours. This often results in delays, wastage of material, and energy-intensive reprocessing when defects are found.

Addressing this challenge, Sheikh Junaid Fayaz, a PhD scholar under the supervision of Prof. N.M. Anoop Krishnan at IIT Delhi's Civil Engineering Department, has developed AI models that cut the error rate by 88% compared to existing industrial methods and deliver results in just 1/100 of a second."X-ray-based clinker checks can take up to four hours, while our AI models can predict clinker quality in just 1/100 of a second—making quality control a million times faster," said Prof. Krishnan. "Real-time accuracy allows engineers to adjust plant parameters proactively, ensuring the target quality is met before production, rather than reacting to delayed X-ray analysis."

Job scam: Man arrested for impersonating Delhi government officials

Agency New Delhi.

A 27-year-old man was apprehended for allegedly duping advocates and educated women under the pretext of providing jobs. He duped two women, including an advocate, by impersonating several government officials.The accused, identified as Sagar Singh, a resident of Ghaziabad in UP and a B.Com graduate, maintained details of various jobs in the several departments, including MHA, and carried out profiling of their department heads online. "He approached the victims by either claiming close connections with these officials or by impersonating senior officers, assuring them that he could arrange jobs for them," a senior police

officer said.A case was registered on Monday based on the statement of complainant Shikha Tiwari alleging that on June 10, she received a message from a woman advocate stating that the accused was competent for providing a job as mentioned in his profile.It was later found that the accused had hacked the advocate's profile and misused it to deceive her into paying money. The complainant also noticed a message sent from the accused's mobile number on June 11, falsely issued in the name of the Education Department, which promised her a women's seat in the Women Commission head office, said Deputy Commissioner of Police (Shahdara) Prashant Gautam.She further received an email stating that any interested person could apply by paying an upfront processing fee of Rs 5,260. On the same day around 8.30 pm, she received another email confirming that her registration had been completed for the seat under the Member of Parliament quota.The email included a registration number and informed her that she was eligible for the next elimination.

1 dead after cloudburst in Uttarakhand's Chamoli; Army joins rescue ops

A cloudburst in Chamoli's Tharali caused massive destruction, leaving one girl dead and one person missing amid debris. Rescue teams and SDRF are carrying out relief operations as roads remain blocked.

Agency New Delhi.

A cloudburst struck Chamoli district, Uttarakhand late Friday night, causing extensive damage across the region. The Tharali market, Kotdeep, and the Tharali tehsil complex were hit hard as large amounts of debris swept through homes, the SDM residence, and other buildings.

Several vehicles parked at the tehsil complex were buried under the debris. The heavy flow of water and debris turned the town's streets into temporary ponds.In nearby Sagwara village, reports indicate that a young girl is dead after being trapped under the debris, causing panic in the area. Local residents rushed out of their homes as rescue and relief operations began.Some shops in Chepdaon market were also damaged by falling debris, and one person has been reported missing, further intensifying the emergency.Expressing concern over the tragedy, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami said he is closely monitoring the situation and is in constant touch with officials overseeing the rescue efforts. In a post on X, he wrote: "Late last night, a tragic report of a cloudburst was received in the Tharali area of Chamoli district. The district administration, SDRF, and police have reached the spot and are engaged in relief and rescue operations. In this regard, I am in constant contact with the local administration and am personally closely monitoring the situation. I pray to God for everyone's safety."

The Tharali-Gwaldam road near Minggedera is blocked due to debris and heavy rainfall, while the Tharali-Sagwara route is also closed, affecting local movement.The Indian Army also confirmed its active role in the rescue mission. In a statement on X, it said: "At

approx 0040 hrs on 23 Aug 25, a mudslide struck Tharali, 25 kms from Rudraprayag in Uttarakhand. The Indian Army has activated HADR columns, medical teams and Search & Rescue Dogs from Rudraprayag and Joshimath. Army detachment at Tharali is already at ground zero, extending immediate rescue & relief. Additional troops & resources from UB Area_IA are being mobilised and joint operations are currently underway with civil administration. The Indian Army stands strong in the face of disaster, committed to saving lives & restoring normalcy."

Amid the devastation, many cars and vehicles were washed away in the catastrophe. A video surfaced from Chamoli in which a distressed man can be heard saying, "Meri car doob gayi" (My car has sunken), reflecting the scale of damage and personal losses suffered by the locals."The police and administration teams are actively engaged in rescue and relief operations," said District Magistrate Dr Sandeep Tiwari.The State Disaster Response Force (SDRF) team has been dispatched from Gauchar to the site. The Border Roads Organisation (BRO) is working near Ming Khedere to clear the road and facilitate traffic and relief operations.

NEWS BOX

Hong Kong rejects renewal of 'Bloomberg' reporter's visa

HONG KONG . (Agency)

A journalist who works for Bloomberg News in Hong Kong said Saturday she has to leave the city after a foreign journalists' club revealed that authorities had denied renewal of her working visa.Rebecca Choong Wilkins, Bloomberg's Asia government and economy correspondent, said on social media that "after six years of reporting in Hong Kong, and at eight months pregnant, I'm very sad to be leaving my colleagues, friends and the place I've called home.""I'll be out of office for a while on maternity leave. Wherever I land, catch you on the other side," she added."We cannot comment on the specifics of her situation but we fully support Rebecca and we will continue to work through the appropriate avenues to try to resolve the matter," a Bloomberg News spokesperson said.Hong Kong's Immigration Department declined to comment on the "individual case" when reached by AFP, adding that it "acts in accordance with the laws and policies in handling each immigration case".The Foreign Correspondents' Club Hong Kong said Friday it was "deeply concerned" over the incident and it understood that authorities did not give any reason for the denial.The decision and the lack of explanation reinforce widespread concerns about the erosion of press freedom in Hong Kong, it said.Last year, another Bloomberg reporter Haze Fan, who is a Chinese national, was refused a visa to work in Hong Kong, media reports said.

4.4 magnitude earthquake jolts Eastern Nepal, no damage reported so far

KATHMANDU .(Agency)

An earthquake of 4.4 magnitude struck Eastern Nepal, officials have said. According to the National Earthquake Monitoring and Research Centre, the tremor of 4.4 magnitude hit Sankhuwasabha district at 11:15 pm on Friday with its epicentre located at Maghang area.The earthquake was also felt in several districts in Eastern Nepal, though there were no immediate reports of casualties or damage, officials said.

Nepal, which lies in a high seismic risk zone, frequently experiences earthquakes. In April 2015, a devastating 7.8-magnitude quake killed nearly 9,000 people and damaged over half a million houses across the Himalayan nation.

After Brother Erik, Lyle Menendez Denied Parole In Parents' Murder

World . (Agency)

A US judicial commission denied parole Friday to Joseph Lyle Menendez, a day after his brother Erik was also ordered to stay in prison for the murder of their parents in a Beverly Hills mansion more than three decades ago.A California panel ordered the 57-year-old, who goes by his middle name, to remain behind bars along with his younger sibling, defying a campaign for their freedom waged by family, friends and celebrities including Kim Kardashian. "Joseph (Lyle) Menendez was denied parole for three years at his initial suitability hearing today," read a brief statement from the California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR).

The outcome of Lyle Menendez's hearing is the latest blow to a movement that has swelled in recent years, amplified by Netflix's smash hit dramatic series "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story."

The show and myriad documentaries have fixated on the gory details of the 1989 shotgun murders, and the televised jury trial that captivated audiences with accounts of their abusive upbringings and posh lifestyles.An 11-hour hearing

Friday's hearing came just over 36 years after the deaths of parents Jose and Kitty Menendez, in what prosecutors said was a cynical attempt by their sons to obtain a large family fortune.After setting up alibis and trying to cover their tracks, Erik and Lyle shot Jose Menendez five times with shotguns, including in the kneecaps.Kitty Menendez died from a shotgun blast as she tried desperately to crawl away from her killers.The brothers initially blamed the deaths on a mafia hit, but changed their story several times in the ensuing months.Erik, then 18, confessed to the murders in a session with his therapist. The pair ultimately claimed they had acted in self-defense after years of emotional and sexual abuse at the hands of a tyrannical father.During their decades in prison, changing social mores and greater awareness of sexual abuse helped elevate the men to something approaching cultural icons.Friday's hearing, which was closed to the public, lasted 11 hours. It was held separately to Thursday's hearing for his brother Erik, 54.Both brothers appeared by video link from the San Diego prison where they are being held.The panel members, whose identities was not released by CDCR, quizzed them on their behavior and attitude

Women political prisoners in Belarus face abuse, humiliation and threats of losing parental rights

Independent experts appointed by the United Nations Human Rights Council describe "appalling" conditions for women in Belarusian prisons, with "a blatant lack of accountability for the ill treatment."

TALLINN .(Agency)

Antanina Kanavalava says her four years in a Belarusian penal colony as a political prisoner were filled with a fear and anguish that still haunts her.She nearly lost parental rights to her two young children when she was initially arrested. Her eyesight deteriorated from sewing military uniforms in a dimly lit room. Denied access to even basic needs like feminine hygiene products, she used rags or whatever she could find amid unsanitary conditions."Women in prison go through hell and can't even complain to anyone," Kanavalava, 37, told The Associated Press after her release in December. "The head of the prison told me straight out that people like me should be put against the wall and shot."Belarus has nearly 1,200 political prisoners. While all endure harsh conditions like unheated cells, isolation and poor nutrition and health care, human rights officials say the 178 women behind bars are particularly vulnerable.Pavel Sapelka, a lawyer with the Viasna human rights center, says women are often singled out for abuse and humiliation, threatened with losing their children, and having medical problems ignored.Sapelka cited the case of Hanna Kandratsenka, 30, who died of cervical cancer in February, months after getting her freedom. She was diagnosed in prison but denied early release for treatment, he said.Independent experts appointed by the United Nations Human Rights Council describe "appalling" conditions for women in Belarusian prisons, with "a blatant lack of accountability for the ill treatment."Authoritarian President Lukashenko has ruled Belarus for over three decades, living up to his nickname of "Europe's last dictator" by silencing dissent and extending his rule through elections the West calls neither free nor fair. A harsh crackdown followed a disputed 2020 vote,

when hundreds of thousands took to the streets. Over 65,000 people were arrested, thousands were beaten by police and hundreds of independent media outlets and nongovernmental organizations were closed and outlawed.Opposition figures are either imprisoned or have fled abroad. Among those behind bars is Nobel Peace Prize laureate Ales Bialiatski, the founder of Viasna, and Maria Kolesnikova, an opposition leader. Although Lukashenko has freed over 300 political prisoners in the last year, still others are arrested in a revolving door of repression.U.S. President Donald Trump said last week on social media that he spoke with Lukashenko and encouraged him to release more. On Friday, Lukashenko responded: "Take them, bring them over there."Of the harsh conditions, Lukashenko says Belarus treats inmates "normally," adding that "prison is not a resort."The government has refused to allow international monitors and independent observers into the prisons.

A mother's trauma

Kanavalava was a confidant of opposition leader Sviatlana Tsikhanouskaya, who challenged Lukashenko in the 2020 election but later fled the country amid the subsequent protests.With her husband also jailed, Kanavalava was convicted of "participating in mass riots" and sentenced to 5 1/2 years. Authorities threatened to send her 6-year-old son, Ivan, and 4-year-old daughter, Nasta, to an orphanage at the start of her sentence."For a mother not to see her children for four years is real torture," she told AP.

Pakistani students in US face uncertainty as government reviews anti-American content on social media

ISLAMABAD. (Agency)

\Pakistani students and other visa holders in the United States are facing growing uncertainty as the Trump administration reviews social media for anti-American or extremist content, reported Dawn on Saturday.As part of the broader vetting process, US authorities are reviewing social media activity for any signs of hostility toward US citizens, culture, government, or institutions, the report said.Even minor infractions, political activity, or incomplete documentation could put their stay at risk, added the report.Incidents of traffic violations and campus protests may be reported to the US Department of Homeland Security (DHS), raising alarms among the Pakistani community.A traffic court judge in northern Virginia informed two Pakistani students recently that the courts are now required to share records of traffic violations with DHS, the report said.

We were planning to drive to Chicago, but we've been advised not to, said Yunus Khan, a student from Baltimore, Maryland. "We are on visas, and even a minor mistake could lead to revocation," he said.The Pakistani embassy says it's monitoring the situation, advising caution in political

activities, the report added.Participating in pro-Palestine protests has made Pakistani students anxious. Some of us joined those demonstrations and now we don't know if we can stay or might face deportation, said Samina Ali, also from Baltimore.Mohammad Sajid, a student at George Mason University, said working a part-time job has become difficult.

Pakistanis who received political asylum face even greater concerns. According to the Pakistan embassy in Washington, between 700,000 to a million Pakistanis live in the United States, most as citizens or long-term residents, the report said.However, as many do not register officially, exact numbers are unclear.Pakistan sent 10,988 students to the US in 2024 in comparison to 17,099 from Bangladesh and 16,742 from Nepal. India topped the list with 331,602 students in 2024.

According to Pakistani embassy estimates, the number of Pakistani students has risen to about 12,500 in 2025.Pakistani authorities in Washington are closely monitoring the situation, emphasising the importance of legal documentation, awareness of rights, and caution in political activity, the report added.

Apple Files Lawsuit Against Oppo For Poaching, Stealing Trade Secrets

world. (Agency)

Apple Inc. accused smartphone maker Oppo in a lawsuit of poaching a highly paid member of the Apple Watch team and encouraging him to steal trade secrets for his new job with the Chinese firm.Sensor system architect Chen Shi secretly accessed confidential documents on Apple's health-sensing technologies for Oppo's benefit to develop a competing wearable device before departing Apple in June, according to a complaint filed Thursday in federal court in San Jose, California."Concealing his impending employment with a direct competitor, Dr. Shi set up and attended dozens of one-on-one meetings with Apple Watch technical team members to learn about their ongoing research," according to the complaint.

In addition, "late at night just three days before leaving Apple, Dr. Shi downloaded 63 documents from a protected Box folder," according to the complaint. "He

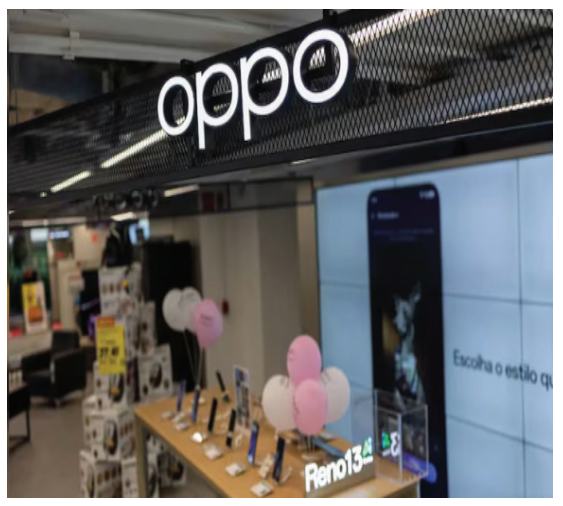

then transferred them to a USB drive one day before his departure."Apple has filed numerous suits in recent years accusing ex-employees and rival companies of breaching contracts and stealing valuable intellectual property. At least three of the iPhone maker's former engineers who worked on its now abandoned electric vehicle autonomous driving project have been criminally prosecuted for allegedly taking secrets to China. The tech giant also has been locked in a court battle with Irvine, California-based Masimo Corp. since 2020 over smartwatch technology.Shi concealed his defection to Oppo, known as Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., by falsely telling his colleagues at Cupertino, California-based Apple that he was returning to China to take care of his aging parents, according to the complaint.Apple says Shi violated a confidentiality and IP agreement, and that Oppo knew of and encouraged his activities.

Tour bus, carrying Indians aboard, crashes on interstate highway in New York, kills 5

The state police said that the driver apparently became distracted, lost control and overcorrected before the bus went into the right shoulder and flipped over shortly

NEW YORK . (Agency)

A tour bus returning to New York City from Niagara Falls with 54 people, including Indians, aboard crashed and rolled on its side on an interstate highway, killing five passengers and injuring many others, authorities have said.The driver apparently became distracted, lost control and overcorrected before the bus went into the right shoulder and flipped over shortly before 12:30 p.m. on the eastbound side of Interstate 90 in Pembroke, New York, about 40 km east of Buffalo, state police Maj Andre Ray said at an evening news conference on Friday (August 22, 2025).He did not say how the driver became distracted, adding that the cause remains under investigation.Mr. Ray said the passengers ranged in age from 1 to 74. Multiple people were ejected from the bus during the crash, and five people — all adults — were pronounced dead at the scene, Mr. Ray said.Many others became entrapped in the wreck and were rescued. Dozens were taken to hospitals. Ray said it didn't appear any other people had life-threatening injuries."An absolute tragedy took place," Mr. Ray said. "And first and foremost, our thoughts, prayers and hearts go out to those involved, their friends and their families." State police said most of the passengers on the bus were of Indian, Chinese and Filipino ethnicity, and authorities brought in translators to help with the emergency response.Mr. Ray said a preliminary investigation ruled out mechanical failure or driver impairment. The driver survived the crash and was cooperating with police, officials said. No charges had been filed as of Friday (August 22, 2025) evening, Mr. Ray said.The Mercy Flight medical transport service said its three helicopters and three more from other services transported people from the crash site. Hospitals in the region said they evaluated or treated more than 40 people. Injuries ranged from head trauma to broken arms and legs.Two people who needed surgery at Erie County Medical Centre in Buffalo were expected to recover, said.

Push to recruit Kurds, religious minorities to Syrian security forces brings both hope and skepticism

AFRIN . (Agency)

Young Kurdish men, including members of religious minorities, recently signed up to join the Syrian government's General Security forces in Afrin, an area in the country's north from which Kurds were forcibly displaced years ago.The push to recruit ethnic and religious minorities comes as the government in Damascus faces increased scrutiny after outbreaks of sectarian violence in recent months during which there were widespread reports of government-affiliated fighters killing and humiliating civilians from the Alawite and Druze sects.A U.N.-backed commission that investigated violence on Syria's coast recommended earlier this month that authorities should recruit from minority communities for a more "diverse security force composition" to improve community relations and trust.Minorities are increasingly wary of the new authorities in Damascus, who are led by Sunni Muslim Islamist former insurgents who overthrew President Bashar Assad in December after a nearly 14-year civil war.An agreement reached in March between Damascus and Kurdish-led forces that control much of northeast Syria also has been on shaky ground.

Seeking a role in the new state

Abbas Mohammad Hamouda, a Kurdish Alawite, was among the young men lining up at a recruitment center in Afrin on Wednesday."I came with young men from my district to join the new state," he said. "We will stand together, united, and avoid problems and wars from now on."The Kurds in Afrin "have been subjected to a lot over the past eight years," Hamouda said, adding, "I hope that the youth of Afrin will not think badly of us because of this affiliation" with the new authorities.

Formerly a Kurdish-majority area, Afrin was seized by Turkish forces and allied Syrian opposition fighters in 2018, following a Turkey-backed military operation that pushed fighters from the Kurdish-led Syrian Democratic Forces and thousands of Kurdish civilians from the area.

Arabs displaced from other parts of Syria have settled in the area since then and the Kurds who stayed have complained of discrimination against them.Some are hoping the recent drive to recruit them to the security forces signals a shift toward more inclusion.Malik Moussa, a Kurd from the Yazidi sect who signed up, said he had come hoping to be "part of the Syrian army and for there to be no discrimination.""We hope that the new government will be for all the people, for there not to be oppression like there was in the past," he said.Ferhad Khurto, a government official responsible for political affairs in the Afrin district, said about 1,000 young men had signed up in recent days to join General Security in the area from "all of its sects and colors and doctrines." He did not give a breakdown of the demographics of the new recruits."This is the first step, and there is a strategy … for the sons of Afrin to share in all the government institutions, not only on the side of internal security but in civilian institutions," he said, adding that the recruitment drive in Afrin is part of a larger national strategy.

NEWS BOX

Which team will play Lionel Messi's Argentina in India Kerala minister answers

New Delhi. (Agency)

Kerala Sports Minister V. Abdurahiman on Saturday said that they are trying to bring a top-tier football team to compete against Argentina in the football friendly that is set to be played in India later this year.On Saturday, August 23, the Argentina Football Association announced that it would be playing an international friendly in India between November 10 and 18. While the opponent has not been announced yet, Kerala's sports minister revealed that multiple football associations have expressed interest in playing against Lionel Messi's side."We will select a team from among FIFA's top 50. Several teams have approached us. The Australian football team has expressed interest, and we also have a sports exchange agreement with them.

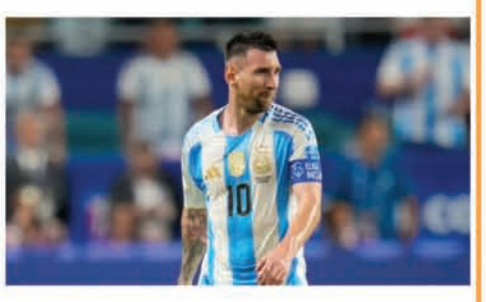

Similarly, three or four other teams have contacted us," Abdurahiman told reporters on Saturday.Abdurahiman revealed that the AFA wanted to play this match in 2026, but the state government requested the federation to schedule the match in either October or November this year."Initially, AFA planned it for 2026. However, we contacted them and requested that they hold the match in Kerala this year. Now, AFA has officially confirmed it. We intend to bring the Argentina squad that won the 2022 World Cup," the minister said.

Expressing his happiness, Abdurahiman added, "A lot of effort has gone into bringing the Argentina football team to Kerala. We have started planning the rest of the arrangements and will soon discuss the details, including the venue, with the Chief Minister."He said several lakh football fans in the state are eagerly awaiting the match. "Our intention is to provide a platform for fans to see Messi play in Kerala," he said.Argentina Set For a Rematch?In case Lionel Messi's Argentina do end up playing Australia in Kerala, it would be a rematch of their 2022 FIFA World Cup clash, where Lionel Messi took apart the opposition with his exceptional game awareness.

Tennis a costly dream Jannik Sinner would have quit if not ranked top 200 by 24

Jannik Sinner has revealed he would have quit tennis if he had not reached the top 200 by age 24. Sinner's comments put light on the financial struggles faced by tennis players from modest backgrounds.

NEW YORK. (Agency)

World No. 1 Jannik Sinner has revealed that he would have quit tennis by the age of 24, if he had not entered the top 200 in the men's singles ranking. Speaking ahead of his first-round game in the US Open, Sinner said that coming from a modest family, it would have been difficult to sustain his sporting endeavours without cracking into the top rankings.Asked about his dream of playing tennis from his childhood days, Sinner stated that he quickly realised that his family would not have been able to sustain tennis unless he himself won enough prize money to take care of his career.Sinner said that he gave himself till the age of 23 or 24 and made peace with the fact that he would quit tennis if he was not inside the top 200 rankings in men's singles competition."I told my parents that if I was not ranked under 200 at the age of 23 or 24, I would stop playing tennis. Because we could not afford it, you know. It costs a lot of money to travel around for tournaments, to have a coach. I was very lucky that I started to earn my money at around 18, and I felt safe. When you are young, you dream, you do not even believe it," Sinner said.Aged 24, Sinner now is the first Italian to win a Grand Slam. He has dominated tennis alongside Carlos Alcaraz for the last few years and is being heralded as the next great. Sinner stated that in many ways he has already outdone his dream and whatever he is getting now is simply a bonus.

"I used to say that I wanted to be World No. 1, I wanted to win a Grand Slam, and it was really just a dream. But the position I am in right now is well beyond my dream. Now it's different, now I understand my potential. But when I was young, if I had been top 100, I would have been the happiest. Everything right now is a big extra," Sinner concluded on the matter.

Jannik Sinner's Family Background

Jannik Sinner's parents, Siglinde and Hanspeter, worked at a ski lodge. His father was a chef and his mother a waitress. Coming from a modest background, the family was aware of the financial challenges associated with competitive tennis, which demands extensive travel and coaching expenses. Despite these hurdles, they committed to nurturing his talent, providing both emotional and practical support.

Jannik's disciplined upbringing and close-knit family environment played a crucial role in shaping his work ethic and determination. His parents' encouragement and belief in his abilities gave him the confidence to pursue a professional tennis career, laying the foundation for his rise in the international tennis world.Sinner is not the first person to talk about the unsustainability of tennis for lower-ranked players. India's top-ranked men's singles player Sumit Nagal had made a shocking revelation in September 2023 that he was left with only Rs 80,000 in his bank account."If I look at my bank balance, I have what I had at the beginning of the year. It is 900 euros (approx Rs 80,000). I did get a bit of help. Mr. Prashant Sutar is helping me with MAHA Tennis Foundation and I also get monthly (salary) from IOCL but I don't have any big sponsor," Nagal had told PTI in an interview.

Won't watch IND vs PAK match, value of human life more than sports: Manoj Tiwary

New Delhi, . (Agency)

Former India cricketer Manoj Tiwary has said that he won't be watching the upcoming India vs Pakistan match in the Asia Cup 2025. India are set to clash with Pakistan on September 14 in Dubai in the continental tournament, which will mark the first cricket match between the two teams after the Pahalgam terrorist attack.Ahead of the fixture, there has been widespread backlash amongst fans, who're against any sporting ties with Pakistan. Recently, Manoj Tiwary also expressed disappointment over organising the upcoming fixture, saying that everyone has forgotten about innocent civilians killed in Pahalgam."I am a little surprised that this match is going to happen. After the Pahalgam attack, in which so many innocent civilians were killed, and then the war that followed, a lot of talk was going on that this time we will give a befitting reply. Despite this, after a few months, everything has been forgotten. I find it hard to believe that this match is happening, that the value of a human life can be zero," Tiwary told ANI.Furthermore,

Tiwary reiterated that human life should be more valuable than sports and stated that he won't be watching the match at all.

"What do they want to achieve by playing with Pakistan? The value of a human life should be more than sports. There is no question of me watching the match at all," he added.The Indian government continues to remain firm on its stance of not having any bilateral sporting relations with Pakistan. However, this restriction does not extend to multilateral tournaments, such as the World Cups and the Olympics, where both countries participate under the jurisdiction of international governing bodies. These tournaments are held in neutral or third-party venues, ensuring no direct bilateral arrangements and maintaining a politically neutral environment for competition.Recently, Pakistan's hockey team declined to travel to India for the Asia Cup Hockey, scheduled to begin on 28 September in Rajgir. Meanwhile, India and Pakistan could clash thrice in the Asia Cup, first in the group stages, second in the Super 4 and the possibility of a final as well.

Rinku Singh opens up on Asia Cup selection: Did not think I would make it

New Delhi. (Agency)

IIndia batter Rinku Singh did not expect to get selected in the Asia Cup 2025 squad. Speaking to RevSportz on the sidelines of the UP T20 League, Rinku said that he was not sure of his selection due to his recent form slump in international and domestic cricket.

After being named in the Indian squad, Rinku scored his maiden T20 hundred. The batter found his form at the crucial time, helping his team – Meerut Mavericks – chase down a target of 168 runs. Rinku's knock came at a time when Meerut were reeling under pressure, having lost four back-to-back wickets inside the first 8 overs of the game."I got motivated after I saw my name on the Asia Cup list. I did not do well last year, and I felt that it was possible that I would get left out. But the selectors showed trust in me and selected me and that gave me a confidence boost. The innings that I played in the UP T20 League has boosted my confidence and I would take it there," Rinku Singh said.The

specialist finisher stated that the fact that he could bowl 1 or 2 overs in a match might have helped in his selection. Rinku revealed that the selection committee is currently showing preference to players who are multi-skilled in nature."Bowling is very important today. The selectors want you to have multiple roles in the team. If you cannot affect the game by bat, do it with the ball," Rinku said.Rinku also spoke about his role in the Indian team and the Kolkata Knight Riders. He hinted that being well regarded for his abilities in the final four overs of the match has perhaps typecast him. Rinku stated that he had the ability to bat much higher up the order but was willing to execute any role that was given to him.

I batted at No. 5 in 2023. I do not feel good when I bat at No. 7 and No. 8. But it is the team's need, so you have to perform in that role. I have played 33 T20I matches for the Indian team and I have scored 3 fifties.

Shubman Gill set to miss Duleep Trophy due to illness: Reports

New Delhi. (Agency)

India's Test captain Shubman Gill is set to miss the Duleep Trophy 2025, scheduled to begin on Thursday, August 28, at the BCCI Centre of Excellence Ground in Bengaluru, as he continues to recover from illness at his home in Chandigarh.According to a report in Cricbuzz, Gill, who was named captain of the North Zone side, recently underwent a medical evaluation by team physiotherapists, with the health report submitted to the Board of Control for Cricket in India (BCCI).With Gill unavailable, vice-captain Ankit Kumar is expected to take over leadership duties, while Shubham Rohilla has been drafted into the squad as his replacement.Meanwhile, Arshdeep Singh

and Harshit Rana, who are both part of India's Asia Cup 2025 squad, will only feature in the opening match against East Zone before leaving for national commitments in the UAE. Gurnoor Brar and Anuj Thakral have been lined up as their replacements.

North Zone squad for Duleep Trophy

Shubman Gill (c), Shubham Khajuria, Ankit Kumar, Ayush Badoni, Yash Dhull, Ankit Kalsi, Nishant Sindhu, Sahil Lotra, Mayank Dagar, Yudhvir Singh Charak, Arshdeep Singh, Harshit Rana, Anshul Kamboj, Auqib Nabi, Kanhaiya Wadhawan (wk).Shubham Arora (wk), Jaskaranvir Singh Paul, Ravi Chauhan, Abid Mushtaq, Nishunk Birla, Umar Nazir, Divesh Sharma

Shubman Gill set for Asia Cup journeyGill was recently appointed as the vice-captain of India's T20 side for Asia Cup, to be held in the UAE from September 9 to 28, with India kicking off their campaign against UAE on Wednesday, September 10.

Fresh from his sensational performance during the Test series in England, Gill tallied 754 runs across five Tests at an average of 75.40, registering four centuries and rewriting the record books as only the first Asian to surpass 700 runs in a single English series.

WWE: Piper Niven stuns Charlotte Flair in shocking SmackDown upset of 2025

SmackDown delivered a major shock as Piper Niven pinned 18-time champion Charlotte Flair in one of WWE's biggest upsets of 2025 to secure her career-defining singles win.

New Delhi. (Agency)

SmackDown this week had one of those "did that really just happen?" moments when Piper Niven pinned Charlotte Flair in the middle of the ring, pulling off what might just be the biggest upset of 2025 so far. For anyone who follows WWE closely, this was a shocker because on paper and throughout historical records, Flair's numbers were seen to absolutely dwarf Niven's, but when Charlotte Flair has one of the wildest resumes in wrestling history. She's a record 18-time champion, with reigns across Raw, SmackDown, NXT, and even a Women's Tag Team Title run. Not to mention that she's also a two-time Royal Rumble winner (2020 and 2024), a multiple-time WrestleMania headliner, and has main-evented more pay-per-views than any other woman in WWE history. Heading into 2025, Flair's win record sits at 18 wins

with 16 singles wins, and the losses incurred were in tag team matches only, making her one of the most dominant competitors ever.the final bell rang, the underdog's hand was raised.Piper Niven, on the other hand, came into this match with a very different story. She's known more for her power moves and teamwork compared to singles. Her biggest success so far was winning the Women's Tag Team Titles with Chelsea Green in 2023, and before this win, she hadn't picked up a major singles victory on SmackDown in over a year. Her singles win percentage across televised matches has hovered around 46.1%, making this victory against Flair a massive leap forward.

The match itself was all about timing. With Alexa Bliss absent from ringside, Charlotte didn't have her usual tag partner watching her back. This easily opened the door for Alba Fyre and Chelsea Green to interfere, and a crucial eye rake from Green left Flair wide open. Niven wasted no time, hit her with a devastating slam, and finally secured the three count, ultimately pinning an 18-time champion clean in the middle of the ring.

US women keep reaching Slam finals and claiming titles. Can an American man win the 2025 US Open

NEW YORK . (Agency)

If there's such a thing as momentum from tournament to tournament in tennis, the American men have some right now.Taylor Fritz, Ben Shelton, Frances Tiafoe and Tommy Paul certainly are getting within reach of ending the country's unprecedented Grand Slam men's title drought, so maybe they're finally ready to win one of those trophies — if anyone other than Jannik Sinner or Carlos Alcaraz is ever going to again, that is — at the U.S. Open, which gets going Sunday."We have a really strong group. We're closer; the closest we've been in a long time," said Fritz, a 27-year-old from California who is seeded No. 4 in New York and was the the runner-up to Sinner there a year ago. "We have several players who are at the caliber it takes to win a Grand Slam title. We're very close. But that last little bit is obviously the hardest part of it."

Fritz's appearance in the 2024 U.S. Open final was the first time in 15 years that a man from the United States even earned the right to play for a major singles championship. Fritz, No. 6 Shelton, who is 22, and No. 17 Tiafoe, 27, each has participated in Slam semifinals twice; No. 14 Paul, 28, has been that far once."Taylor getting to the final of the U.S. Open is going to fuel Tommy, Ben and Frances. ... That's always the way it's been with this generation: They spark each other," said U.S. Davis Cup captain Bob Bryan, a 16-time Grand Slam doubles champion who is being inducted into the International Tennis Hall of Fame on Saturday. "They see themselves making the final of a Grand Slam now. It is not unattainable. It's not impossible."All four have spent time in the top 10. Indeed, when Shelton cracked that milestone in June, he joined Fritz and Paul to give their nation three representatives in that elite group for the first time since 2006.

Now what's missing is that elusive trophy.

"I can't wait for it to happen," Shelton said Friday, "and we kind of move on to a different question."U.S. women keep winning Slam trophies and appeared in the last four finalsAmerican women,

meanwhile, occupy four of the top nine places in the WTA rankings and five of the top 11. They keep earning spots in title matches — at least one has participated in each of the past four Slam finals, winning two."The women have been carrying for a very, very long time," Fritz acknowledged with a smile.It helped, of course, to have Serena Williams — 23 major singles championships — and Venus Williams — seven — but there also were titles collected by Coco Gauff, Madison Keys, Sofia Kenin and Sloane Stephens since 2017.

Now, perhaps, it's the men's turn?

"For sure, there's going to be a lot of hype around them going into the U.S. Open," said Jessica Pegula, the American who was the runner-up to No. 1 Aryna Sabalenka at Flushing Meadows last year. "I know they love playing there and want to do well there, too."Been quite a while, as everyone knows: Andy Roddick's U.S. Open triumph in 2003 was the most recent Slam title anywhere for a man from the country — a fact the current crop has heard more often than they'd care to remember.

DND Sreeleela Surapaneni

Has Signed Off For The Day Amid Her Busy Schedule

Sreeleela is preparing to make her Bollywood debut shortly. When she is not working, the actress frequently shares details about her personal life with her admirers. In the latest, the actress uploaded a mirror image of herself hinting that she has wrapped up after a long and tiresome day. In the caption, she wrote "DND signing off." Not much about the location was revealed in the picture. Sreeleela's face was hidden by the phone and only her eyes could be seen.Sreeleela is gearing up for Anurag Basu's next alongside Kartik Aaryan. According to Mid-Day, the film's last shooting schedule would begin in Mumbai following the Ganesh Chaturthi celebrations. "The bulk of the film is already shot. Post Ganpati celebrations this month, the team will dive into a 45-day marathon schedule that should take the movie to the finish line," the source revealed. The film's release date was originally set for Diwali 2025, but that has since changed. Anurag Basu revealed earlier in July that the release date will be pushed back, and it is now expected to open in April 2026.

Sreeleela's Big Bollywood Break

Earlier in February, the makers unveiled the first peek at the untitled film, which comprised bits of Sreeleela and Kartik's romance sequences, giving fans a glimpse of their on-screen chemistry.

Sreeleela's Upcoming Projects

According to recent reports, Sreeleela may join Ranveer Singh and Bobby Deol in an untitled mega-project. However, there is presently no official confirmation. Moving on, Sreeleela is preparing for her forthcoming film, Junior, in which she will appear alongside Kireeti Reddy. Sreeleela began acting as a young artist in 2017. Later, she played the lead in the Kannada film Kiss in 2019, setting the stage for her Telugu debut, Pelli SandaD, in 2021.

She starred in Dhamaka, which earned her the SIIMA Award for Best Actress – Telugu. She has appeared in the movie Skanda, Aadikeshava, Extra Ordinary Man and Guntur Kaaram.

Nikki Tamboli

Strongly Reacts To Usha Nadkarni's Remarks: 'Just Because You Are Senior...'

Nikki Tamboli and Usha Nadkarni did a show together, Celebrity MasterChefs, but they didn't gel well on the show. In a recent podcast, the veteran actress, who is known for her show Pavitra Rishta, talked about Nikki Tamboli's behaviour and said that she thinks she is a big star and doesn't talk to anyone. While her sharp criticism left Nikki's fans upset, the actress herself has now condemned Usha Nadkarni's words in a strong yet respectful way.Nikki Tamboli has responded with dignity and poise to senior actress Usha Nadkarni's recent remarks. While making it clear that she holds immense respect for the veteran star, Nikki also set the record straight about her own personality and the love she shares with her fans.

Speaking with heartfelt clarity, Nikki said, "I have huge respect for Usha ji. Just because you are senior and I am junior, and I don't flatter you or say yes to everything, doesn't mean you can say anything about me. Please don't judge me as egoistic—I know my personality and so do my fans. Apart from the respect I have for you, no one else has the right to judge me."

The actress, who first shot to fame for her spirited personality on Bigg Boss, reminded everyone that her journey hasn't been an easy one."It's not easy to come out as the first runner-up in such a tough show. But I did it by being myself. It's not in my nature to flatter people for acceptance. My fans love me for the person I truly am, and that emotional bond with them is my real strength," Nikki added.

What Usha Nadkarni Said?

In a recent podcast with Pinkvilla, when asked about Nikki Tamboli, Usha Nadkarni made a face showing her dislike and said, "She is a huge star, according to her; in her eyes, we are nobody, so let's not talk about her. I don't talk too much to big people, because they don't talk, and she never mixed around."

About Usha Nadkarni

Usha Nadkarni rose to fame with Pavitra Rishta, produced by Ektaa Kapoor, wherein she essayed Sushant Singh Rajput's mother. She played a negative character, yet won universal appreciation from fans and was very close to Sushant in real life.

She appeared on reality shows too, such as Bigg Boss Marathi 1, and also on Celebrity MasterChef, wherein she got eliminated prior to the semi-finals. Besides Pavitra Rishta and Thodi Si Zameen Thoda Sa Aasmaan, Nadkarni has featured in hit TV serials such as Kaise Mujhe Tum Mil Gaye, Kuch Is Tara, and many more.

Fatima Sana Shaikh Declares Jaipur Her Happy Place And We Agree

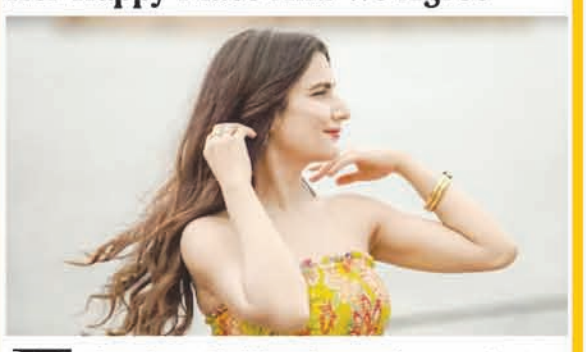

Fatima Sana Shaikh, who was last seen in Aap Jaisa Koi opposite R Madhavan, is currently in Jaipur. Although it is unclear whether she is in the Pink City for a film promotion or not, one thing is certain: the actress is having a gala time at the destination. On Friday, August 22, Fatima shared a set of pictures on Instagram, exploring Jaipur, which grabbed the attention of fans and travel enthusiasts alike.The opening frame captured Fatima Sana Shaikh posing for a candid picture against a scenic background. She looked pretty, dressed in a yellow strapless midi dress featuring floral prints in multi-hued shades. A sleek belt was wrapped around her waist, adding an extra dose of functionality to her OOTD. Fatima paired her avatar with golden accessories, minimal makeup and open, wavy hair.

Fatima Sana Shaikh's Jaipur Adventures

In the following slide, Fatima Sana Shaikh was seen enjoying a rickshaw ride in the city. She smiled ear-to-ear in the snap. The last photo showed the actress taking a selfie against the backdrop of what appeared to be a fort. Her side note read, "Jaipur is one of my favourite cities! I have only scratched the surface, and there is still so much left to explore (red heart emoji)."

Fatima Sana Shaikh's Himachal Pradesh Vacation

Fatima Sana Shaikh is a true-blue traveller. Nearly a week ago, the actress uploaded a carousel of pictures on Instagram, offering fans a peek into her Himachal Pradesh getaway. The post was a photo dump from her vacation back in April. From wandering through the tree-clustered forests and indulging in a myriad of delicacies to simply soaking in the beauty of the destination, Fatima's sojourn was picture-perfect.She captioned the post, "A massive photo dump from the mountains. I feel happier in the mountains." Fatima Sana Shaikh hashtagged the post with the words "pahadi ladki".Workwise, Fatima Sana Shaikh was seen in two movies this year. The first one was Anurag Basu's Metro In Dino, which was the sequel to the 2007 hit Life In A Metro. Apart from that, Fatima appeared in the Netflix romantic drama Aap Jaisa Koi, which received critical acclaim.

Jacqueline Fernandez Adopts Stray Cat Amid Supreme Court's Order: 'Wish This For All...'

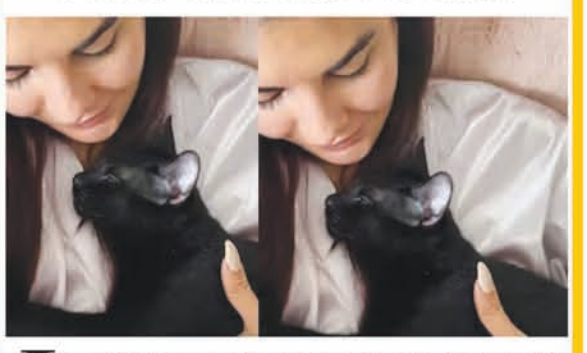

Jacqueline Fernandez has again won hearts with her kind gesture. The actress recently adopted a stray cat from Delhi, and the act has been widely appreciated on social media.Her action coincides with a recent Supreme Court judgment on how stray dogs must be dealt with. In this context, her gesture of offering shelter to a stray animal is being interpreted as a powerful message of kindness and responsibility.

Jacqueline's Message to Fans

Fernandez went to Instagram to share an emotional encounter with her new furry friend. She posted a photo of herself on Story cuddling the cat. "From the streets to a home. Wish this for all strays".

The post was soon trending as fans loved her compassion for voiceless creatures. The emotional message spread love and kindness among animal lovers throughout the nation.Jacqueline has been a long-time vocal supporter of animal rights. Adopting the cat is not merely a personal gesture of goodwill but also a public declaration that puts the spotlight on the importance of empathy.

Fans Shower Love Online

The actress' performance elicited an eruption of praise across social media. Social media sites were swamped with comments applauding her humanity. A commenter wrote, "She's so sweet!! Such a nice celebrity ", with others overrunning timelines with clapping emojis and compliments.

To many of her fans, taking in a stray was not only about providing shelter but also about inspiring millions to treat animals with compassion. Fans labeled her as "inspiring" and "caring," providing a model for how celebrities can help society in a positive way.

Commitment to Animal Welfare

The adoption tale of Jacqueline is not a singular act. The years have seen her standing up for animal rights causes and espousing humane treatment of animals. This latest action only adds to her reputation as a star espousing causes that are not necessarily glamorous.

Her remark — "wish this for all strays" — is a soft reminder that all stray animals are worthy of a loving home and safety.

In adopting a stray cat, she has reaffirmed the notion that compassion can be an effective force for change.In a nation where the welfare of stray animals remains a perennial issue, Jacqueline's act is more than a celebrity newsflash. It is a heartwarming appeal.